कामकाजी महिला

वर्ष 4 अंक 2 दिसंबर, 1991 मूल्य : 2 रु०

अजेय समाजवाद

की

अमर ज्योति

लेनिन

समाजवाद अजेय है

विमल रणदिवे

अक्टूबर क्रांति की 74वीं वर्षगांठ हमारी जनता तथा देश भर का मजदूर वर्ग 7 नवंबर को कॉ. लेनिन के नेतृत्व में 1917 की ऐतिहासिक घटना को और अधिक उत्साह व दृढ़ता से मनायेगा। समाजवाद तथा मार्क्सवाद-लेनिनवाद में हमारी श्रद्धा के प्रतीक लाल झंडे और बैनर सभा स्थलों पर लहरायेंगे। मजदूर रूसी क्रान्ति के प्रमुख नियंता लेनिन को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए शोषण की पूंजीवादी व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष करने की शपथ लेंगे। यह विश्व का पहला मजदूर-राज्य था जिसका उदय 1917 में किसानों व मजदूरों के संगठन से हुआ था। अक्टूबर क्रान्ति ने पूंजीवादी देशों के शोषित तबके को उम्मीद बंधाई थी कि वह वैज्ञानिक समाजवाद को अपना कर तथा वर्ग संघर्ष चलाकर अपने शोषण को समाप्त कर सकता है। मजदूर वर्ग की तानाशाही की स्थापना अन्य मित्रवत् वर्गों की सहायता से हो सकती है। भारत तथा अन्य देशों में मजदूर वर्ग ने महसूस किया कि समाजवाद सपना नहीं बल्कि वास्तविकता है। सोवियत संघ हमारा मित्र होगा जो मजदूर क्रान्ति के लिए आजादी हासिल करने में हमारी मदद करेगा। और उसने मदद की। मजदूर-राज्य ने सत्ता में आते ही क्या कदम उठाये ?

क्रान्ति के बाद काम का अधिकार, भूमिहीनों की भूमि, मुफ्त शिक्षा, महिलाओं को गर्भावस्था-लाभ तथा क्रेच की सुविधाएं सबसे पहले प्रदान की गयीं। फैक्ट्रियों में महिलाओं द्वारा खतरनाक काम करने पर रोक लगा दी गयी। महिलाओं को मताधिकार देना, विवाह तथा तलाक की प्रक्रिया को सरल बनाना तथा वैध व अवैध बच्चों का भेद समाप्त करना भी सर्वहारा सरकार के पहले कामों में थे।

कामकाजी महिलाएं तथा सभी आम महिलाओं को 1917 की अक्टूबर क्रान्ति की उपलब्धियों पर गर्व है। क्रान्ति में कामगार महिलाओं की शानदार भूमिका की लेनिन ने प्रशंसा की थी। दरअसल; ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार; "रूसी क्रान्ति का आरम्भ 8 मार्च को

इस अंक में

समाजवाद अजेय है	2
संसद में सुशीला गोपालन का वक्तव्य	6
आंगनवाड़ी महिलाओं को लाभांश का वादा	7
साम्यवाद पुनः उभरेगा	7
राजस्थान में कामकाजी महिला समन्वय समिति का गठन	8
साहिबगंज में जनवादी महिला समिति इकाई की स्थापना	9
एक और दहेज हत्या	10
न्याय की खोज में मुन्नी देवी	10
पूर्वी जर्मनी के मजदूरों का कठोर भविष्य	11
संयुक्त संघर्ष समिति का प्रतिनिधिमंडल वित्तमंत्री से मिला	11
उदयपुर में ब्याही मनीषा को दहेज लोभियों ने जलाकर मार डाला	12
क्रान्ति का पहला दिन—महिला दिवस	13
सरकार के मुकरने की सांसदों द्वारा निन्दा	16
पांडिचेरी आंगनवाड़ी महिलाओं का बोनस के लिए अनशन	17
नगर निगम में महिलाओं के लिए 30 प्रतिशत सीटें	17
27 सितम्बर को शानदार दिल्ली मार्च	18
प्रथम जीवन बीमा निगम कामगार महिला सम्मेलन	19
अमरीका में बिगड़ती सामाजिक स्थिति	21
तंजावूर क्षेत्र में कामगार महिला सम्मेलन	22
महिलाओं पर अत्याचार की भर्त्सना	23
महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध	23
उजन मैदान कांड के लिए सरकार को दोषी ठहराया	24

सीटू के अखिल भारतीय कामकाजी महिला समिति के लिए विमला रणदिवे की ओर से 6, तालकटोरा रोड, नई दिल्ली-110001, (फोन नं० 384071) से सम्पादित और प्रकाशित तथा प्रोग्रेसिव प्रिंटर्स, ए-21, झिलमिल इंडस्ट्रीयल एरिया, शाहदरा, दिल्ली में मुद्रित।

अंतर्राष्ट्रीय महिला समारोह के रूप में हड़ताल तथा जुलूस से हुआ था।" रोटी के लिए संघर्षरत हजारों महिलाओं ने उनका साथ दिया तथा भोजन व बेहतर वेतन की मांग की। लाल झंडे लिए दो बच्चियों द्वारा बटालियन में प्रवेश कर जाने तथा अपने संघर्षरत भाइयों पर पर गोली न चलाने की अपील करने की कहानी ने हमेशा महिलाओं को प्रेरणा दी है। "कोसाक अमर रहें के नारे के साथ वापस लौटीं। लेनिन ने कहा था कि "कामगार महिलाएं, जो कि समाज का सबसे दलित वर्ग हैं, मुक्ति की व्यापक राह से कभी अलग नहीं रह सकतीं तथा वे मजदूर वर्ग की शक्ति का सबसे बड़ा स्रोत हैं।" सर्वहारा क्रान्ति का भविष्य इस पर निर्भर करता है कि यह स्रोत उसके साथ होता है या नहीं। अनेक महिलाएं शहीद हुईं व कई घायल हुईं लेकिन उन्होंने पुनः आगे बढ़कर सत्ता प्राप्ति के लिए किये जा रहे प्रदर्शन में भाग लिया। क्रान्ति के बाद महिलाओं ने शोषण से पूरी तरह मुक्ति प्राप्त की।

74वीं वर्षगांठ के अवसर पर हम क्रान्ति की नायिकाओं को गर्व से याद करते हैं जिन्होंने पहली सर्वहारा क्रान्ति को सफल बनाने के लिए पूरी शक्ति से योगदान दिया। विश्व भर के सर्वहारा की आंखें रूस पर लगी हुई थीं जो कि जमींदारी व पूंजीवादी व्यवस्था के अंतर्गत शोषियों के भविष्य के लिए आशा थी। मजदूर वर्ग की मुक्ति तथा समाजवाद की स्थापना के लिए संघर्ष का मूल सिद्धांत मार्क्सवाद-लेनिनवाद था।

लेकिन रूस के अन्दर मौजूद शत्रुओं तथा बाहर मौजूद साम्राज्यवादी शक्तियों ने सर्वहारा क्रान्ति का मतलब अच्छी तरह से समझ लिया तथा उन्होंने हर तरफ से नवोदित राज्य पर हमले आरंभ कर दिये। लेकिन वे लेनिनवाद के नेतृत्व वाले मजदूर वर्ग व उसकी पार्टी के आगे सफल न हो सके।

द्वितीय विश्व-युद्ध में हिटलर की घोर पराजय

22 जून 1941 को हिटलर ने अपनी दुर्जेय शक्ति के साथ सोवियत पर आक्रमण कर दिया। सोवियत जनता नाजी आक्रमण से अपनी मातृभूमि को बचाने के लिए एक होकर उठ खड़ी हुई। 1418 दिनों तक देश के चप्पे-चप्पे में भयंकर युद्ध चला। द्वितीय विश्व युद्ध में में मारे गये 5 करोड़ लोगों में 2 करोड़ सोवियत संघ से जिन्होंने अपने देश व अन्य अनेक देशों की रक्षा के लिए थे (जो हिटलर के सफल होने पर शिकार बनते) अपनी जानें कुर्बान कर दीं। भारत तथा अन्य देशों के मजदूर वर्ग कम्युनिस्ट पार्टियों व विश्व भर की नजरें लेनिनग्राद, मॉस्को व अन्य स्थानों पर चल रहे संघर्ष पर टिकी थीं। जब हिटलर को अपने सैनिकों व टैंकों सहित बर्लिन की ओर भागना पड़ा तो विश्व भर में प्रगतिशील जनता में खुशी की लहर दौड़ गयी थी। सोवियत सैनिकों ने बर्लिन पहुँचकर वहाँ की संसद पर लाल झंडा फहरा दिया। सोवियत भूमि पर सोवियत व नाजी सैनिकों के बीच आखिरी लड़ाई दरवाजों-दरवाजों पर सोवियत संघ की एक-एक इंच भूमि वापस लेने के लिए लड़ी गयी। हिटलर की सेना को परास्त करने के लिएरणनीति बनाने में दिशानिर्देश करने वाले स्टालिन, वोरोशिलोव जैसे महा पुरुष थे। स्टालिन के इन अन्तिम शब्दों ने, कि, हिटलर की कब्र मॉस्को में खुदेगी, सोवियत संघ को आखिरी दम तक संघर्ष करने के लिए प्रेरित किया गया। हिटलर सेना के हमले तुला तथा नोवोफोमिस्क पर रुक गये थे जहाँ उन्होंने मास्को पर कब्जा करने के लिए सुरक्षा चक्र को भेदने की आखिरी कोशिश की थी। प्रति आक्रमण रोस्तोव के कस्बों तथा बाद में मॉस्को में हुआ। चार माह के अन्दर सोवियत सेना ने नाजियों को 150-100 किलोमीटर तक वापस खदेड़ दिया। यह नाजी जर्मनी की प्रमुख हार थी। लेनिनग्राद के सफल युद्ध के बाद इस शहर का नाम यहाँ के लोगों के शानदार युद्ध के कारण 'हीरो सिटी' रखा गया था।

स्टॉलिनग्राद का युद्ध

स्टालिनग्राद का युद्ध सोवियत सेना के विजय पथ पर एक मील का पत्थर था। सारे विश्व ने वोल्गा पर लड़े गये इस युद्ध को सांस रोक कर देखा। कम्युनिस्ट पार्टी ने युद्धरत लोगों से स्टालिनग्राद का समर्पण न करने के लिए कहा तथा वे बलपूर्वक डटे रहे। युद्ध का अन्त 2 फरवरी 1943 को हिटलर की पूर्ण पराजय के रूप में हुआ। 1944 में अन्तिम नाजी घुसपैठियों को सोवियत भूमि से बाहर किया गया।

इन बातों को कौन भूला सकता है? दुर्भाग्यवश सोवियत संघ में कुछ नेता हैं जो चाहते हैं हम स्टालिन के योगदान को भूल जायें। हम उसे नहीं भूलेंगे, भले ही उनसे

जीवन में कुछ गलतियाँ हुई हों ।

1945 में नाजी जर्मनी के खिलाफ सोवियत देश भक्तों की चालीसवीं वर्ष गांठ के अवसर पर स्वीकार किया गया था कि "सोवियत जनता इसलिए विजयी हुई क्योंकि उसने वैचारिक रूप से कम्युनिस्ट पार्टी का अनुसरण किया । इस विजय का श्रेय कम्युनिस्ट पार्टी को है ।" वक्तव्य में आगे कहा गया है कि नाजियों के ऊपर विजय समाजवादी अर्थव्यवस्था, मार्क्सवाद-लेनिनवाद, सोवियत देशभक्ति, सर्वहारा अंतर्राष्ट्रीयतावाद के लिए एक महान विजय थी । (श्रमिक संघों की अखिल संघ केन्द्रीय परिषद, मॉस्को 1985)

गोर्बाचोव व येल्सतिन के अनेक समर्थक हो सकते हैं जो कई मुद्दों पर कॉ स्टालिन को गालियाँ देते हैं । लेकिन उन्हें यह मानना पड़ेगा कि यदि द्वितीय विश्वयुद्ध के समय स्टालिन का मार्गदर्शन उपलब्ध न होता तो सोवियत संघ व अन्य बहुत से देशों का अस्तित्व भी न होता ।

कॉ. लेनिन के नेतृत्व में हुई सोवियत क्रान्ति एक बार पुनः समाजवाद के सिद्धांत व रणनीति को सही साबित करती है और वर्तमान में सोवियत नेता कुछ भी कहते रहें हैं हम उस सिद्धांत का अनुसरण करते रहेंगे ।

द्वितीय विश्व युद्ध ने अन्य देशों में समाजवाद को जन्म दिया

द्वितीय विश्व युद्ध ने पूर्वी यूरोप में समाजवाद को जन्म दिया । वे सोवियत सैनिकों व खुद उन देशों के सैनिकों के मार्च के साथ एक के बाद एक स्वाधीन होते चले गये । 20 अक्टूबर 1944 को यूगोस्लाविया, 1945 में ही रोमानिया, बुल्गारिया व चेकोस्लोवाकिया स्वतंत्र हुए । बाद में चीन में समाजवाद आया । एक छोटा-सा देश, वियेतनाम, वर्षों तक अमरीका के खिलाफ संघर्ष करता रहा तथा अन्त में वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी व उसके नेता हो ची. मिन्ह के नेतृत्व में सफल हुआ । कोरिया व क्यूबा ने मार्क्सवादी सिद्धान्त के अंतर्गत समाजवाद की स्थापना की । इन घटनाओं ने समाजवादी व्यवस्था को दृढ़ता प्रदान की तथा साम्राज्यवाद के खिलाफ शान्ति के लिए विश्व में शक्ति संतुलन को बदल दिया । सोवियत संघ व अन्य समाजवादी राष्ट्रों की सैनिक शक्ति साम्राज्यवादी अमरीका के मुकाबले में आ खड़ी हुई । समाजवादी व्यवस्था व समाजवादी खेमे ने विश्व भर के दलित वर्ग के लिए एक ढाल की तरह काम किया । उन्हें सोवियत संघ से वैचारिक, सैनिक व अन्य प्रकार की सहायता का आश्वासन मिला ।

सोवियत संघ में हाल के घटनाक्रम के बाद स्थिति बदली

सोवियत संघ तथा पूर्वी यूरोप में हाल में घटी घटनाओं ने पूरे विश्व के नक्शे को बदल दिया है । गोर्बाचोव-येल्सतिन गुट ने समाजवाद तथा मार्क्सवाद-लेनिनवाद को समाप्त करने की घोषणा कर दी । कॉ. स्टालिन को 1955-56 में ख्रुश्चेव द्वारा निशाना बनाया गया था, तथा अन्य लोगों ने विश्वास था कि गोर्बाचोव समाजवाद से बढ़कर हैं; 'पूंजीवादी राह' पर चलने का निश्चय किया । यह हमारे देश की प्रगतिशील जनता के लिए एक बड़ा धक्का था कि सभी कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव, गोर्बाचोव ने स्वयं कम्युनिस्ट पार्टी व केन्द्रीय समिति पर प्रतिबंध लगा दिया, फंड व संपत्ति जब्त कर ली, तथा सरकारी पत्र प्रावदा (सत्य) का प्रकाशन बन्द कर दिया । कोई जांच कर सकता है कि उन्हें यह सब करने का अधिकार किसने दिया ? यह देखकर पीड़ा होती है कि महान लेनिन, स्वर्डलोव, 1917 के महान क्रान्तिकारी अक्रोम्येव, की प्रतिमाएं ध्वस्त कर दी गयीं और मजदूर वर्ग की ओर से कोई प्रतिरोध नहीं हुआ । कब्रों से शव खोदे गये हैं । लाल झंडे को फाड़ डाला गया । स्टालिनग्राद, लेनिनग्राद व मॉस्को के नाम बदलकर पुराने जारकालीन नाम ले आये गये हैं । मैक्सिम गोर्की मार्ग हट गया है, लेकिन उनके उपन्यास 'माँ' की स्मृति हमारे दिलों में मौजूद है ।

यह दुर्भाग्यपूर्ण था कि गोर्बाचोव व अन्य नेता यह भूल गये हैं कि यह स्टालिन और केवल स्टालिन ही थे जिन्होंने सोवियता संघ को नाजी घुसपैठ से बचाया । क्या स्टालिन के इस योगदान को हम भुला सकते हैं, इस बात को स्वीकार करते हुए भी उनसे कुछ गलतियाँ हुई थी ? यह कोई आश्चर्य नहीं है क्योंकि गोर्बाचोव के शब्दकोश में 'साम्राज्यवाद' शब्द था ही नहीं ।

सोवियत जनता द्वारा झेली गयीं विकट परिस्थितियाँ

यह सच था कि पिछले लगभग चार वर्षों से सोवियत

जनता को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था, और प्राप्त रिपोर्टों के मुताबिक देश की आर्थिक स्थिति अभी भी वैसी ही बनी हुई है। महिलाओं को आवश्यक वस्तुओं, जिनकी बाजार में कमी थी, के लिए लम्बी कतारों में खड़ा होना पड़ता था। कालाबाजारी फल-फूल रही है। हमारे दूसरे विश्व-युद्ध के समय के ऐसे अनुभव हैं जब महिलाओं को राशन प्राप्त करने के लिए घण्टों कतार में खड़ा होना पड़ता था। जब 1989-90 में मॉस्को में ऐसी परिस्थिति का सामना करना पड़ा तो हमारी 1940 की बंगाल के अकाल की याद ताजा हो गयी। लेकिन उस समय हम अंग्रेजी राज में रह रहे थे। लेकिन यहाँ समाजवाद के अंतर्गत महिलाओं को खाद्य-सामग्री के लिए घंटों लाइन लगानी पड़ती थी। उन्हें रोजगार की जरूरत नहीं रह गयी थी। वे घर रह कर घर के काम-काज तथा बच्चों की देखभाल करना चाहती थीं। सोवियत नेता व 'प्रावदा' अपने लेखों में यह उपदेश दे रहे हैं महिलाओं का स्थान घर के अन्दर है। वर्तमान में झेली जा रही अनवरत समस्याओं के बीच लेनिन की सीख को भुला दिया। यह मेरे लिए एक अनुभव था जब मैंने मास्को सभा में एक महिला को यह कहते सुना कि वह घर रह कर परिवार-पेंशन लेना चाहती हैं। उनकी साथियों ने भी उनके इस विचार का समर्थन किया। भारत, लातीनी अमरीका, फ्रांस, कांगो तथा अन्य देशों ने इस बुर्जुआ विचारधारा का विरोध किया। यह एक तथ्य है कि पिछली गलतियों को सुधारने के लिए अपनायी गयी पेरेस्त्रोइका व ग्लासनोस्त की नीतियों से ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई। महिलाएं घरेलू काम के बोझ तथा राशन के लिए कतार लगाने से बेशक ऊबती हैं। रोजगार के जरिये आर्थिक स्वाधीनता के महत्व को आज नहीं देखा जा रहा है। हमारे यह पूछने पर कि क्या उसने 'लेनिन-मुसोलियम' देखा है, हमारे दुभाषिये ने हंसते हुए कहा— "नहीं। वहाँ देखने को है ही क्या? शव को तो कभी का दफना दिया गया होगा।" हालांकि यह सुनकर मेरा खून खौल उठा लेकिन मैंने उससे कहा कि यदि हमारे यहाँ के लोग ऐसा सुनें तो उन्हें गुस्सा आ सकती है व उन्हें इस पर विश्वास ही न हो। सोवियत संघ में अब महिलाओं को सीने पर अमरीकी बिल्ले पहनने में गर्व का अनुभव होता है। नयी पीढ़ी का पतन, अमरीका व पश्चिमी संस्कृति की प्रशंसा करने, तक हो चुका है।

उस तथा इस जैसे अन्य अनेक उदाहरणों से पता चलता है कि पेरेस्त्रोइका व ग्लासनोस्त के नारों का क्या परिणाम हुआ है। हालांकि ये नारे कुप्रबंध व प्रशासन में व्याप्त अफसरशाही से उत्पन्न परिस्थितियों के समाधान के नाम पर दिये गये थे लेकिन इन्होंने सोवियत जनता को बर्बादी के कगार पर ला खड़ा किया है।

प्रमुख विरोधाभास को भुला दिया जाना

गोर्बाचोव के भाषणों व अखबारों में प्रकाशित उनकी रपटों में साम्राज्यवाद का उल्लेख नहीं है। न ही वे ऐसा करना चाहते हैं क्योंकि वर्तमान सोवियते नेतृत्व के विचार से समाजवाद और साम्राज्यवाद में कोई विरोध नहीं है। पहले ही, 1987 में, 'नयी सोच' के नाम पर 'विरोधों के सुधार' की विचारधारा अपना ली गयी। चिन्ता का प्रश्न यह है कि यदि प्रमुख शत्रु—अमरीकी साम्राज्यवाद, को भुला दिया गया तो क्यूबा व लातीनी अमरीकी देशों का क्या होगा जो साम्राज्यवाद का शिकार हैं। अब समाजवादी क्यूबा को लेकर गोर्बाचोव और बुश में सौदेबाजी हो रही है। यदि सोवियत संघ क्यूबा को दी जाने वाली सारी सहायता बन्द कर दे तो गोर्बाचोव को आर्थिक मदद मिलेगी। मौंकाडा वर्षगांठ पर क्यूबाई पार्टी के नेता फिदेल कास्त्रो ने घृणापूर्वक कहा था, "वे चाहते हैं कि हम पूरी तरह से बदल जायें और हम ऐसा कभी नहीं करेंगे···क्रान्ति न अपने आदर्श बदलती है न ही अपना नाम···" का. कास्त्रो को कितना गर्व था, बावजूद इस तथ्य के क्यूबा के अमरीका द्वारा घिरे होने के कारण उन्हें अपनी जंग अकेले लड़नी पड़ेगी। चीन, वियतनाम, कोरिया, पुर्तगाल व कई अन्य देशों की कम्युनिस्ट पार्टियों ने कहा है कि वे समाजवाद तथा मार्क्सवाद-लेनिनवाद के समर्थन में ही रहेंगी। मजदूर वर्ग जानता है कि केवल समाजवाद के अन्तर्गत ही लोगों को शिक्षा, रोजगार आवास व अच्छा जीवन मिल सकता है।

मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी व देश के अन्य प्रगतिशील संगठन मार्क्सवादी-लेनिनवादी विचारधारा में दृढ़ विश्वास रखते हैं तथा सोवियत संघ में गोर्बाचोव द्वारा फैलायी गयी बुर्जुआ विचारधारा के बावजूद वे पूंजीवादी व्यवस्था के खात्मे तथा समाजवाद की स्थापना के लिए संघर्षरत रहेंगे।

अपने देश का अनुभव

हमारे देश की जनता का चालीस वर्षों का अनुभव यह साबित करता है कि जब तक हम कांग्रेस के पूंजीवादी, बुर्जुआ जमींदारी शासन के खिलाफ वर्ग संघर्ष नहीं छेड़ेंगे तब तक हम समाजवाद की ओर ले जाने वाली लोकतांत्रिक जनक्रांति की राह पर अग्रसर नहीं हो सकेंगे। हमारे देश में बेरोजगारों की तादाद 3 करोड़ तक पहुंच गयी है, 2 लाख से अधिक फैक्ट्रियां बन्द हैं तथा कीमतें आसमान छू रही हैं। आधुनिक तकनीक की पहली शिकार महिलाएं हैं। सरकारी क्षेत्र के निजीकरण की घोषणा हो चुकी है। इसका अर्थ है कि हमारा देश अमरीका को बेचा जा रहा है। मार्क्सवाद-लेनिनवाद तथा वर्ग आधार पर पूंजीवाद के विरुद्ध संघर्ष किये बगैर यह स्थिति नहीं बदलेगी। केन्द्र की वर्तमान अल्पमत सरकार मुद्रा कोष व विश्व बैंक की शर्तों को स्वीकार कर ही चुकी है। केन्द्रीय श्रम संगठन कांग्रेस (ई) सरकार की इन नीतियों के खलाफ संघर्ष कर रही हैं व उन्होने मजदूरों से 29 नवंबर को हड़ताल रखने की अपील की है।

हम सोवियत संघ. चीन व वियतनाम जैसे समाजवादी देशों से मार्गदर्शन व सहायता की उम्मीद करते आये हैं। दुर्भाग्यवश सोवियत संघ व पूर्वी यूरोप के देशों ने अब समाजवाद को छोड़कर पूंजीवाद का रास्ता चुन लिया है। लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि वर्तमान स्थिति अधिक समय तक नहीं रहेगी। सोवियत जनता गोर्बाचोव व जनता को धोखा देने वाले अन्य नेताओं की इस प्रतिक्रान्ति के खिलाफ उठ खड़े होंगे। इसमें समय लग सकता है। लेकिन लोग अपने अनुभव से अपने अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए उठ खड़े होंगे। वे यह महसूस करेंगे कि पूंजीवादी व्यवस्था उन्हें कोई लाभ नहीं देगी तथा भविष्य में मार्क्सवादी सिद्धांतों पर आधारित कम्युनिस्ट पार्टी का गठन होगा। आखिर मार्क्सवाद एक विज्ञान है। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद व अन्य चीजें अपना समय लेंगी।

संयुक्त जर्मनी का अनुभव

प्राप्त तथ्यों के आधार पर, जर्मनी के एकीकरण का अनुभव यह बताता है कि संघर्ष आरंभ हो चुका है। रोजगार व आवास आदि के लिए प्रदर्शन आरंभ हो चुके हैं। "हम एक हैं" के नारे के साथ जर्मनी का एकीकरण हुआ था। अब प्रदर्शनों में यह नारा है कि "क्या हम एक हैं?" सोवियत संघ में भी लोगों ने सोचना आरंभ कर दिया है। वहाँ से आ रही रपटों से पता चलता है कि वर्तमान शासन के अंतर्गत सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है।

हम इस 7 नवंबर, महान अक्तूबर क्रान्ति की 74वीं वर्षगांठ पर, सोवियत जनता के लिए विशेष रूप से सोवियत महिलाओं के लिये यह कामना करते हैं कि वे अजेय समाजवाद के मार्क्सवादी-लेनिनवादी रास्ते पर आगे बढ़ें, जो उन्होंने हमें 1917 में दिखाया था।

संसद में सुशीला गोपालन का वक्तव्य

"....बिना क़िसी पूर्व संदर्भ के आप 'महिला अधिकार आयुक्त की बात कर रहे हैं। श्री राजीव गांधी के समय में महिला संगठनों का एक सम्मेलन बुलाया गया था, लेकिन उसका परिणाम क्या निकला? 'महिला अधिकार आयुक्त' के प्रस्ताव का सबने विरोध किया था और अब कांग्रेस पार्टी वही प्रस्ताव पुनः ला रही है। मेरे विचार से केन्द्र में महिला आयोग देश भर में महिलाओं की समस्याओं को सुलझाने के लिए काफी नहीं है कि हमारे समाज में अभी सामंतवादी रवैया बरकरार है। पढ़ी लिखी महिलाएं भी सती के समर्थन में बोल रहीं हैं, और वह भी इस सदन में। हमने भी देखा है। ऐसी घटनाएं घट रही हैं। अतः केन्द्र में महिला अधिकार आयोग स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। सभी राज्यों में महिला आयोग का गठन होना चाहिये तथा उसका जिला स्तर पर संपर्क होना चाहिये देश की महिलाओं की सहायता हो सकेगी। उस समय हमारा विषय पर बहुत विचार-विमर्श हुआ था व कांग्रेस पार्टी सहमत नहीं हुई थी। अब वे पुनः वही प्रस्ताव ला रहे हैं। सदन ने प्रावधान पास कर दिया है। उन्हें लोकतांत्रिक तौर-तरीका का विचार नहीं है। यह एक महत्वपूर्ण कमी है व इस पर सहमत नहीं हो सकते। हमें इस पर महिला संगठनों के साथ विचार-विमर्श करना चाहिये व एक आयोग का गठन होना चाहिए, जैसाकि लोकसभा में प्रावधान पास हुआ था। यह देश के महिला संगठनों की मांग है।

महोदय, इन सब कारणों से मैं इस विषय का विरोध करती हूँ। कृपया इन चीजों के लिए हमारी पार्टी से सहयोग की उम्मीद न रखें। यदि आप अपना विचार बदलने को तैयार हों तभी कुछ हो सकता है।

आंगनवाड़ी महिलाओं को लाभांश का वादा

आंगनवाड़ी (महिलाओं) कर्मचारियों की समस्याओं को अवगत कराने हेतु 'अखिल भारतीय आंगनवाड़ी कर्मचारी महासंघ का प्रतिनिधिमण्डल संसद सदस्या का० मालिनी भट्टाचार्य की अगुवाई में वित्तमंत्री माननीय श्री मनमोहन सिंह से मिला। उनकी प्राथमिक मांगें थी कि इन सेविकाओं को, जो कि सामाजिक क्षेत्र में लाभकारी उद्योगों में कार्य करती है—स्थायी नियुक्ति की जाए तथा सरकारी कर्मचारी के रूप में स्वीकार किया जाए। वर्तमान समय में इन कर्मचारियों को जो सुविधाएं हैं वह आवश्यकता से बहुत कम है, इसलिए जब तक कि व्यवस्था स्थिर न हो जाए तब तक इन कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन दिया जाए। जिसका प्रावधान वर्तमान बजट में हो। क्योंकि जरूरतमंद वस्तुओं की कीमतों में असाधारण वृद्धि को देखते हुए इतने कम वेतन पर इन कर्मचारियों को कार्य जारी रखना असंभव है।

डा० मनमोहन सिंह ने इन कर्मचारियों को स्थायी रूप से नियुक्त करने में अपनी असमर्थता व्यक्त की। लेकिन हमारे प्रतिनिधिमण्डल द्वारा काफी दबाव डालने पर, आंगनवाड़ी कर्मचारी और सेविकाओं को वर्ष 1991-1992 में कुछ सुविधाएं देने के सम्बन्ध में मंत्री महोदय सहमत हुए। सरकार के वक्तव्य से ज्ञात होता है कि वह आई. सी. डी. एस. उद्योग और उसमें कार्यरत कर्मचारियों के सहयोग की सराहना करता है। उन्होंने फेडरेशन के प्रतिनिधिमण्डल को यह भी आश्वासन दिया कि आंगनवाड़ियों के निजीकरण का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि यह तो सरकार का सामाजिक दायित्व है।

अखिल भारतीय आंगनवाड़ी कर्मचारी महासंघ की कार्यकर्त्ता और महिला सांसद कुछ मध्यवर्ती सहायता देने के विषय में दबाव डालते रहेंगे, जब तक कि आर्थिक विषय पर पूरी बहस नहीं हो जाती। आंगनवाड़ी कर्मचारियों की सरकारी कर्मचारी के बराबर स्थान मिले, इसके लिए तत्पर रहेंगे।

विमला रणदिवे, द्वारा जारी प्रेस वक्तव्य

साम्यवाद पुनः उभरेगा

नीना आंद्रेयेवा

लेनिनग्राद, 10 सितंबर (ए. पी.)। मार्क्स व लेनिन की विरासत नष्ट होने पर आंसू न बहायें। समाजवादी की सच्ची समर्थक नीना आंद्रेयेवा का कहना है कि समाजवाद का पुनः उदय होगा और वे ही इस बदलाव का नेतृत्व करने वाली हो सकती हैं।

'हम एक सच्ची मार्क्सवादी-लेनिनवादी पार्टी के उदय की बात कर रहे हैं', सोवियत संघ की बुजुर्ग मार्क्सवादी-लेनिनवादी नेता ने कहा।

अपने विचारों में आंद्रेयेवा के समान दृढ़, कम ही कम्युनिस्ट हुए हैं। सुश्री आंद्रेयेवा तीन साल पहले मिखाइल गोर्बाचोव के सुधारों का मुखर विरोध करने वाली प्रथम पार्टी सदस्या थीं।

यद्यपि यह एक वैचारिक चुनौती थी लेकिन कम्युनिस्टों द्वारा ही आलोचना से यह कमजोर हुई व एक ऐसे आन्दोलन को बल मिला जिसकी परिणति 18 अगस्त को गोर्बाचोव व उनके सहयोगियों के विद्रोह में हुई।

सुश्री आंद्रेयेवा कहती हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी अपनी सीमा पर पहुंच गयी। उसने समाज की नजरों में अपनी साख खो दी तथा वह नेतृत्व करने अथवा कोई ठोस काम करने में असमर्थ हो गई। अतः ग्यारह मिलियन कम्युनिस्ट वास्तव में कम्युनिस्ट कहलाने के हकदार नहीं हैं। उन्होंने कहा कि "इससे बेहतर दो या तीन मिलियन लोग होते हैं जो समाजवाद के प्रति वाकई समर्पित होते।"

कुछ नाम उनके दिमाग में हैं। विद्रोह के एक माह पहले उन्होंने 'बोल्शेविक प्लेटफॉर्म' का गठन किया था, व उसमें गोर्बाचोव की नीतियों की तीखी भर्त्सना की थी।

सुश्री आंद्रेयेवा ने कहा, "उन्होंने मुझे ही नहीं पूरी सोवियत जनता को धोखा दिया। सुश्री आंद्रेयेवा की योजना नवंबर में कम्युनिस्ट पार्टी के नाम से एक पार्टी गठित करने की है।"

राजस्थान में कामकाजी महिला समन्वय समिति का गठन

मधु सेठिया

राजस्थान में कामकाजी महिला समन्वय समिति के काम को संगठित करने के लिए दिनांक 8.9.91 को जयपुर में विभिन्न यूनियनों को प्रतिनिधि महिलाओं की एक मीटिंग आयोजित की गयी जिसमें, आंगनबाड़ी बीड़ी श्रमिक शिक्षक संघ तथा वन विभाग श्रमिकों की प्रतिनिधि तथा जयपुर गंगानगर व बीकानेर की कार्यकर्ता महिलाओं ने भाग लिया, अ. भा. कामकाजी महिला समन्वय समिति की संयोजक कॉ. विमल रणदिवे तथा राज्य सीटू के महामन्त्री का. रविन्द्र शुक्ला की मीटिंग में उपस्थित थे।

का. शुक्ला ने मीटिंग में बताया कि सीटू के राज्य कमेटी ने निर्णय लिया है कि कामकाजी महिलाओं की एक राज्य स्तरीय समन्वय समिति संगठित करने का निर्णय लिया है। इस उद्देश्य से सर्व प्रथम हम अपने प्रभाव क्षेत्रों में जो महिलाएं कार्यरत है, इनकी समस्याओं व इस दिशा में उनकी यूनियनें क्या करती हैं, यह जानना चाहते हैं।

ब्यावर की बीड़ी श्रमिकों ने बताया कि उनकी यूनियन बनने के बाद से उन्हें कार्ड मिले हैं, मातृत्व कालीन लाभ के रूप में 250/- रुपये मिलता है, परन्तु मातृत्व कालीन अवकाश अभी तक लागू नहीं हो पाया है, कार्ड में मजदूरी व प्राविडेन्ड फण्ड की प्रविष्टि नहीं की जाती है तथा 1000 बीड़ी की मजदूरी 18.62 तय है, परन्तु उन्हें मात्र 16.50 प्राप्त होता है।

आंगनबाड़ी की महिलाओं का कहना था कि अभी भी बिना कारण सेवा मुक्ति तथा अफसर-शाही जारी है तथा सुपरवाईजर के रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता नहीं दी जा रही है। शिक्षक संघ की बहिनों का कहना था कि ग्रामीण क्षेत्रों में महिला शिक्षकों को भारी कठिनाईयाँ उठानी पड़ती है, उन्हें लम्बी दूरियों की यात्रा पैदल व बसों से करनी पड़ती है, तथा आवासीय व घरेलू असुविधा भी झेलनी पड़ती है। निजी शिक्षक संस्थाओं में अधिकांशत: निर्धारित वेतन से बहुत कम दिया जाता है तथा मातृत्व कालीन लाभ तो प्राय: नहीं मिलता।

गंगानगर की श्रमिक महिलाओं में कार्यरत का. दुर्गा ने बताया कि खेत मजदूर महिलाएं आज भी जमींदारों का दुर्व्यवहार सहती है।

रूई बीनने का रेट 1/- रुपये की बजाय 60-70 पैसा मिला है, इन्हें संगठित करने के प्रयास किये गये हैं। उन्होंने यह भी कहा कि सीटू आंगनबाड़ी तथा जीनिंग की महिलाओं में कोई रूचि नहीं लेती है, बीकानेर की का. अणिमा ने बताया बीकानेर के पापड़ उद्योग की महिलाओं ने मशीनें लगाये जाने का विरोध किया है, परन्तु यह आन्दोलन स्फतः स्फूर्त था, और वे महिलाएँ अभी भी संगठित नहीं हैं, ऊन उद्योग में लगी महिलाएँ भी यूनियन बनाने से डरती है। यही कारण है कि इन उद्योगों में हजारों की संख्या में महिलाएँ होने के बावजूद भी उनकी स्थिति दयनीय बनी हुई है।

अन्त में का. विमल रणदिवे ने श्रमिक प्रतिनिधियों व कार्यकर्ताओं को सम्बोधित करते हुए कहा कि महिलाओं का शोषण देश के सभी स्थानों में व्याप्त है हमें उससे संगठित होकर लड़ना पड़ेगा। वर्तमान परिस्थिति में कुछ भी लेने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ेगा हमें संगठन पर भरोसा है सरकार पर नहीं, उन्होंने अ० भा० कामकाजी महिला समन्वय समिति की पिछली मीटिंग के निर्णयों की भी जानकारी दी।

अंत में का. शुक्ला ने अ. भा. कामकाजी महिला समन्वय समिति की राज्य ईकाई के निर्माण के लिये प्रयास करने हेतु एक समिति बनाने का प्रस्ताव रखा, जिसमें 21 सदस्य हो 3 आंगनबाड़ी 3 शिक्षक, 3 बीड़ी, 2 बैंक कर्मी, 2 एल. आई. सी., 1 जी. ई., वन विभाग, 1 कोटा इन्सट्रूमेन्टेशन, 1 अन्य व 1 संयोजक, इसमें का. पुष्पा शर्मा, जसपाल कौर, सुशीला शर्मा, दुर्गा स्वामी, मंजु, कमला, भगवती, गायत्री, अणिमा, नानगी को सम्मिलित किया गया। है तथा शेष स्थान अभी रिक्त हैं, समिति की संयोजक का. मधु सेठिया को बनाया गया।

साहिबगंज (वाराणसी) में जनवादी महिला समिति इकाई की स्थापना

जनवादी महिला समिति ने 26-10-91 को चखौरा तहसील में एक रैली का आयोजन किया जिसकी मुख्य अतिथि का० विमल रणदिवे। रैली की अध्यक्षता चित्रा बनर्जी ने की। बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय की रीडर डा० रामकली भी मौजूद थीं। रैली में 1000 महिलाओं ने भाग लिया। वे दूर-दराज के इलाकों ट्रैक्टरों व ट्रकों के अलावा पैदल भी आयीं। पूरा जिला महिला समिति के बैनरों से सजा हुआ था। डा० होशीला मंच की संयोजक थी। साहिबगंज महिलाओं के इस प्रदर्शन से चकित था, संभवत वह महिलाओं शक्ति से थोड़ा भयभीत था। बहुत से लोगों ने इसे प्रगति के प्रतीक के रूप में देखा तथा जनवादी महिला समिति को इसका श्रेय दिया। ध्वजारोहण के बाद का० रामानन्द ने भाग लेने के लिए आये सभी सदस्यों का स्वागत किया।

महिलाओं को अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा देते हुए का. आशा ज्योति ने कहा कि 'महिला-जागृति' प्रशंसनीय है और इसकी ओर से सबसे पहले जनवादी महिला समिति का ध्यान गया है। तदोपरान्त का. यशोदा ने खान मजदूरों के संघर्ष का विवेचन कि जिससे महिलाओं में उत्साह पैदा हुआ। सभी महिलाओं ने पुलिस व प्रशासन की मिली भगत को समझा। का. रामकली ने कहा कि "बीसवीं सदी में भी भारत में महिलाएं गुलाम हैं।" उन्होंने एक महिला मुक्ति-कार्यक्रम को रेखांकित किया। सरोज कुशवाहा ने महिला मुक्ति पर एक कविता पढ़ी तथा का. सुशीला देवी महिलाओं की समस्याओं के बारे में बोली।

सदस्यों का अभिनंदन करते हुए का. विमल रणदिवे ने कहा कि अब महिलाएं अबला नहीं सबला हैं। इस विचार की और स्पष्ट करने के लिए उन्होंने रोजमर्रा के जीवन से उदाहरण दिये। मूल्य-वृद्धि, दहेज, शिक्षा व साम्राज्यवाद सभी ने महिलाओं को संघर्ष के लिये प्रेरित किया है। यदि महिलाएं इसी प्रकार संघर्ष जारी रखें तो वे स्वयं अपने भविष्य का निर्माण करेंगी। उन्होंने त्रिपुरा व पंजाब में महिलाओं द्वारा दिखाई गयी हिम्मत का जिक्र किया। सायं 4 बजे प्रतिनिधि अधिवेशन आरंभ हुआ, जिसमें 400 महिलाओं ने भाग लिया। सबीना बेग़म, विमल कुशवाहा सहित कॉ. चम्पा देवी संयोजक थीं। संघर्ष में शहीद हुए लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की गयी।

27-10-91 को ए. आई. एल. यू. के नेता श्री प्रसाद ने सदस्यों को संबोधित किया। उन्होंने कहा "भारत में महिलाएं पिछड़ी हुई हैं। हालांकि वे अपनी चूड़ियों के ही समान नाजुक हैं, लेकिन उनमें तलवार का पैनापन भी है।"

सचिव द्वारा रपट रखी गयी, जिस पर हुई बहस में 5 महिलाओं ने भाग लिया। 'जनम' ने भी महिलाओं को बहस में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया। अंत में आयोजकों को धन्यवाद देने के साथ ही सत्र समाप्त हुआ।

निम्नलिखित प्रस्ताव पास किये गये—

1. त्रिपुरा में महिलाओं पर अत्याचार
2. पंजाब पर प्रस्ताव
3. 'चकिया' की आत्मनिर्भरता तथा समबद्ध विकास पर प्रस्ताव
4. प्रशासन द्वारा महिलाओं की मांगें पूरी करने पर प्रस्ताव
5. आंगनवाड़ी महिलाओं की समस्याओं पर प्रस्ताव

छात्रों, सीटू व अन्य बिरादराना संगठनों ने भी महिला समिति के कार्यक्रम के प्रति समर्थन व्यक्त किया। उन्होंने महिलाओं से संगठन को मजबूत करने व 'महिला-शिक्षा' पर अधिक ध्यान केन्द्रित करने का आग्रह किया।

सीटू के कॉ. बनर्जी ने मिलकर अपनी समस्याओं पर विचार करने के लिए महिलाओं की प्रशंसा करते हुए कहा कि "अपने बारे में आपकी गलतफहमी दरअसल आप पर पूंजीपतियों द्वारा थोपी गयी है जिन्होंने आपको भाग्यवाद से बांध दिया है। क्योंकि केवल इसी प्रकार वे आपकी सम्पत्ति को चुरा सकते हैं। राम जन्म-भूमि आन्दोलन चलाकर भाजपा आपके अंध-विश्वासों का लाभ उठा रही है। भाजपा आपको वास्तविक संघर्ष से भटका रही है।"

उन्होंने भाजपा तथा पश्चिम बंगाल की वाम-मोर्चा सरकार की नीति की तुलना की तथा महिलाओं व बच्चों से संबंधित नीतियों पर विशेष बल दिया। हरिजनों व मजदूरों के दमन के विरूद्ध संघर्ष करते हुए पुलिस की गोलियों का डटकर मुकाबला करने के लिए महिलाओं की प्रसंशा की।

कॉ० विमल रणदिवे ने कहा कि "अपने दिल से भय को निकाल दो। जमींदारों का सामना करो। दमन के विरूद्ध संघर्ष करना आसान नहीं है। अब श्रमिक वर्ग को जातिगत आधारों पर बांटा जाता है। जमिन पर काम करने वालों को जमीन का मालिक होना चाहिये। यह एक लम्बा संघर्ष है।" अंत में उन्होंने त्रिपुरा फंड, सांप्रदायिक सद्भाव व संगठन को मजबूत बनाने की अपील की।

एक और दहेज हत्या

गोविन्दपुर, बिहार थाने के अन्तर्गत परासी गांव के सतीश मंडल की पुत्री रीता मंडल को उसके ससुराल वालों ने दहेज के लिए जलाकर मार डाला।

इसकी खबर समाचार पत्रों से फैली। खबर पढ़कर जनवादी महिला समिति की संध्या बक्शी परासी गांव पहुंची। वहां छानबीन करने पर ज्ञात हुआ कि दहेज की मांग को पूरा न कर पाने के कारण रीता के पति, सास, ससुर व ननद ने खाने में जहर मिलाकर उसकी हत्या कर दी। अभी तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है।

बेटी की मौत की खबर पाकर उसके पिता सतीश, चाचा पतित, भाई भक्तिपद और दामाद धीरज मंडल उसके ससुराल पहुँचे व शव के पोस्टमार्टम कराये जाने का अनुरोध किया। इस पर उन लोगों को मार-पीट के बाद कमरे में कर दिया गया व इस दौरान शव का दाह संस्कार कर दिया।

रीता मंडल के परिवारजनों ने एक पत्र लिखकर उपायुक्त से अपराधियों को गिरफ्तार करने व उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करने की मांग की है, साथ ही पत्र में चेतावनी दी गयी है कि यदि दोषियों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो जनवादी महिला समिति आंदोलन पर मजबूर हो जायेगी।

न्याय की खोज में मुन्नी देवी

मुन्नी देवी ने 1986 में महिला स्वास्थ्य सेविका के रूप में सरकारी नौकरी की। उसकी प्रथम नियुक्ति मुरैना जिले में हुई। यहीं से उस पर हुए जुल्मों की कहानी शुरू होती है। इस स्वार्थी दुनिया में डॉ० एम. एस. मंगल ने खलनायक की भूमिका अदा की। जब उसे पहली बार वेतन दिया गया तो उन्होंने उससे आधा वेतन बांटने को कहा। जब उसने ऐसा करने में असमर्थता व्यक्त की तो उसका मासिक वेतन छह वर्ष के लिए रोक दिया गया। जब उसने मामले की ऊपर शिकायत की तब भी उसे न्याय नहीं मिला। ऐसा प्रतीत होता है कि उच्च अधिकारी भी वेतन अधिकारी से मिले हुए हैं। उन्होंने शिकायत को नहीं सुना तथा उसकी समस्याओं व व्यथा की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। हमें यह मानना पड़ा कि आजकल महिलाओं के उत्थान के लिए दिये जाने वाले नारे कोरे नारे हैं। वास्तव में महिलाओं का अभी भी दमन व शोषण किया जाता है।

वेतन से वंचित मुन्नी देवी को हस्पताल में दाखिल करना पड़ा जहां उसने जीवन और मृत्यु के बीच संघर्ष किया। संक्षेप में 1988 तक उसे वेतन नहीं मिला तथा उसके लिए भूखा रहना असंभव हो गया।

न्याय पाने के लिए मुन्नी देवी ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया जहां उसकी बात को धैर्य के साथ सुना गया तथा उसकी समस्याओं पर ध्यान दिया गया लेकिन उससे भी कोई लाभ नहीं हुआ। सामाजिक संस्थाएं भी उसे न्याय दिलाने में असफल रहीं। बहादुर व अकेली योद्धा मुन्नी देवी को गुण्डों व असमाजिक तत्वों द्वारा जान से मारने की धमकियां दी गयीं। इसका परिणाम यह हुआ कि मुन्नी देवी दिमागी मरीज हो गयी।

मुन्नी देवी ने अपनी पहली शिकायत 18-10-89 को तत्कालीन प्रधान-मंत्री स्व. श्री राजीव गांधी से, तत्पश्चात् 25-9-90 को तत्कालीन प्रधान मंत्री श्री वी. पी. सिंह तथा 7-1.91 को श्री चन्द्रशेखर से कीं। लेकिन दुर्भाग्यवश देश के उच्चतम अधिकारी उसकी समस्या का समाधान नहीं कर सके।

मुन्नी देवी ने प्रण किया है कि वह इन दुराचारी शक्तियों से अंत तक लड़ेगी व उन्हें उखाड़ डालेगी।

पूर्वी जर्मनी के मजदूरों का कठोर भविष्य

बॉन सरकार द्वारा स्थिति को शान्त करने के प्रयासों के बावजूद जर्मनी के पूर्वी भाग में, लीपजिग में, सरकारी नीतियों में परिवर्तन कराने के लिए हर हफ्ते प्रदर्शन हो रहे हैं।

एक अन्य घटनाक्रम में जर्मनी की विपक्षी 'सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी' ने आर्थिक व सामाजिक संकटों के समाधान के लिए हेल्मुर कोल की सरकार से सहयोग करने के लिए कई शर्तें रखी हैं। एस. पी. डी. अध्यक्ष मंडल ने सरकार में आमूल परिवर्तन की मांग की है। उसने दखल वाली औद्योगिक व क्षेत्रीय नीति रोजगार के अवसर पैदा करने पर अधिक बल (न कि निजीकरण व मिलबंदी), तथा सरकारी जमीन को पुराने मालिकों को सौंपने की योजनाओं को बदलने की मांग की है।

पार्टी के कार्यकारी प्रमुख ऍक फ्यूक्स ने स्पष्ट किया है कि जब तक सरकार वैकल्पिक नीतियाँ नहीं अपनाती तब तक श्री कोल तथा हैंस जोकन वोगल के आयोगों का कार्य नहीं चल पायेगा।

यह टिप्पणियां तब आयी जब सरकार के आर्थिक सलाहकारों ने यह अनुमान प्रगट किया कि वर्ष के अंत तक बेरोजगारी दुगनी यानि 17 मिलियन तक हो जायेगी।

'डेट स्पेगल' पत्रिका के अनुसार पूर्वी जर्मनी के कुल निर्माण उद्योगों में से केवल 20 % अथवा 34 मिलियन में से केवल 700,000 रोजगार बचेंगे।

सरकारी सलाहकारों ने अपनी रपट में चेतावनी दी है कि पूर्वी जमर्नी में वेतन-स्तर को दक्षिण जर्मनी के समान बनाने के ताबड़तोड़ प्रयासों से बेरोजगारी बढ़ेगी। रपट में आगे कहा गया है कि तेजी से लाये गये ढांचागत बदलावों के बावजूद बेरोजगारी को खत्म करने में वर्षों लगेंगे। चांसलर का सुझाव है कि पूर्वी जर्मनी का जीवन स्तर पांच वर्षों में दक्षिण जर्मनी के समान हो जायेगा।

सलाहकारों ने पूर्वी जर्मनी के घाटे के उपक्रमों के सब्सिडी देने व निजीकरण को प्राथमिकता देने के खिलाफ चेतावनी दी। उनका कहना है कि "बाजार अर्थव्यवस्था में कौन सा उद्योग टिकेगा कौन-सा नहीं इसका फैसला संसद में अथवा अफसरशाहों के दफ्तरों में नहीं किया जाता बल्कि, बाजार स्वयं इसका फैसला करता है।"

इससे पता चलता है कि सरकार किस दिशा में बढ़ रही है। रपट में पूर्वी जर्मनी के लाखों-करोड़ों मजदूरों के भविष्य के बारे में कोई टिप्पणी नहीं की गयी है। केवल यह कहना कम होगा कि भविष्य 'कठोर' है।

(अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगनठ केन्द्र से प्राप्त)

संयुक्त संघर्ष समिति का प्रतिनिधि-मंडल वित्त मंत्री से मिला

एन. एफ. टी. यू., एटक, सीटू, एच. एम. एस. व अन्य संगठनों की ओर से देश भर की आंगनवाड़ी महिलाओं का एक प्रतिनिधि मंडल वित्त मंत्री डा० मनमोहन सिंह से मिला। उन्होंने न्यूनतम वेतन व मानदेय में अस्थायी वृद्धि की मांग की। प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व संसद सदस्य का. समर मुखर्जी ने किया। एच.एम. एस. की ओर से का. राजहंस तथा अखिल भारतीय आंगनवाड़ी सेविका सहायिका संघ की ओर से विमल रणदिवे मौजूद थीं। आंगनवाड़ी सेविकाओं व सहायिकाओं को महंगाई के ऐसे समय में केवल 250-300 रु० तथा 110 रु० मिलते हैं। श्रीमती राजकुमारी, (एन. एफ. टी. यू. अध्यक्ष) ने, जो कि स्वयं एक कामगार महिला हैं, आई. सी. डी. एस. योजना के तहत कार्यरत महिलाओं की विकट स्थिति के बारे में जानकारी दी। एन. एफ. टी. यू. के श्री हुकुम सिंह ने उनकी बात को और बल प्रदान किया।

श्रीमती गीता मुखर्जी (सांसद) को अपने प्रश्न का उत्तर प्राप्त हुआ जिसमें वित्त मंत्री ने कहा कि मानदेय की वर्तमान राशि में किसी प्रकार काम चलाना होगा। उसके लिये कामगारों की संख्या या इकाईयों में कटौती की जा सकती है।

चर्चा में हस्तक्षेप करते हुए कॉ. समर मुखर्जी ने कहा कि जब सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के लिये आइ. सी. डी. एस. योजना चलायी है तो इन महिलाओं की मदद करना सरकार का कर्तव्य है। जब उनसे पूछा गया कि प्रतिनिधि मंडल महिलाओं को क्या उत्तर दे तो उन्होंने कहा कि वे दो माह बाद ही बता सकेंगे कि मानदेय बढ़ाया जा सकता है अथवा नहीं।

उदयपुर में ब्याही मनीषा को दहेज लोभियों ने जलाकर मार डाला

उदयपुर, 14 अक्टूबर । यहां पर ब्याही गई जयपुर की एक लड़की मनीषा को गत दिनों उसके ससुराल वालों ने दहेज की खातिर जलाकर मार डाला । मनीषा के पीहर वालों ने ससुराल पक्ष को असरदार व पहुंच वाला बताते हुए जांच कार्य में बाधा डालने का संदेह व्यक्त किया है और मांग की है कि अपराधियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाये ।

जयपुर में दुर्गापुर में रह रहे राधेशचन्द्र शर्मा ने अपनी फरियाद में बताया कि 8 अक्टूबर की देर रात उनकी बहन मनीषा को उदयपुर स्थित उसके ससुराल में उसके पति राजीव जोशी और सास श्रीमती कमला ने 1 लाख रुपये की राशि नही पहुंचाने पर जलाकर मार दिया ।

राधेशचन्द्र ने बताया कि उसकी बहन मनीषा का विवाह 15 फरवरी 1985 को 18 पोलो ग्राउंड उदयपुर निवासी राजीव जोशी, जो कि यहां के बैंक आफ राजस्थान लि. की वेदता शाखा के प्रबन्धक हैं, के साथ हुआ था । मनीषा के पति व राजीव, सास श्रीमती कमला का ब्याह शुरू से ही दहेज को लेकर अच्छा नहीं रहा । हमेशा सोना व नकदी की मांग करते रहे, जिस पर उन्हें रेफ्रिजरेटर, टी. वी., वाशिंग मशीन, सोने की जंजीर, हीरे की अंगूठी, हीरे की गोंग व टप्स तथा महंगे सूट आदि-आदि देकर समय-समय पर मांग पूरी की गई ।

मृतका मनीषा के दो बच्चे भी हैं, के भाई का आरोप है कि मांग पूरी करते रहने से ससुराल वालों ने और अधिक मांग करना शुरू कर दिया और मनीषा व उसके दोनों बच्चों को जान से मार डालने की धमकी दी जाने लगी ।

राधेशचन्द्र शर्मा ने बताया कि हाल ही में 8 अक्टूबर की रात मेरी बहन मनीषा से एक लाख रुपये की मांग की गई, जिस पर उसने मेरे पिता वागेशचंद्र शर्मा को रात दस बजे जयपुर में दुर्गापुर स्थित घर पर टेलीफोन किया और कहा कि उसके पति व सास कई दिनों से एक लाख रुपये मंगाने के लिए कह रहे हैं तथा जान से मारने की धमकी दे रहे हैं ।

राधेशचन्द्र के अनुसार 'मेरे पिताजी ने एक लाख देने में असमर्थता जाहिर की और कहा कि इस समय इतने रुपयों का इन्तजाम नहीं किया जा सकता । 'टेलीफोन आने के बाद देर रात करीब दो-ढाई बजे राजीव जोशी के मामा गोपेश भट्ट का फोन आया कि मनीषा की तबियत खराब है, तुरन्त चले आयें । यह सूचना मिलने पर स्वयं राधेशचन्द्र व दूसरा भाई गोपेशचन्द्र शर्मा हवाई जहाज से 9 अक्टूबर की सुबह करीब 8 बजे उदयपुर पहुंच गये, वहां पता चला कि मनीषा अस्पताल में भर्ती है ।

राधेशचन्द्र के अनुसार अस्पताल में उनकी बहन मनीषा जिसका सारा शरीर जला हुआ था, लेकिन वह होश में थी, उसने बताया कि 'तेरे जीजा जी व इनकी मां ने मिलकर मेरी यह हालत कर दी है । जब मैं चिल्लाई तब किसी को भी अन्दर नहीं आने दिया व दरवाजे बन्द मुझसे कहा कि यह बात तूने किसी से भी कही तो तेरे बच्चों की भी यही हालत कर देंगे ।

मनीषा ने अस्पताल में अपने भाइयों के समक्ष पापा से भी मिलने की इच्छा जाहिर करते हुए पापा को बुलाने का आग्रह किया; लेकिन मनीषा उसके पापा वागेश चन्द्र से बिना मिले चल बसी । वागेश चन्द्र जयपुर से टैक्सी लेकर जब उदयपुर पहुंचे तब तक उनकी बेटी दम तोड़ चुकी थी ।

मृतक मनीषा के भाई राधेशचन्द्र ने ससुराल पक्ष को पहुंच वाला बताते हुए आशंका व्यक्त की है कि वे जांच कार्य में बाधा डालने की कोशिश करेंगे । उन्होंने अपराधियों के विरुद्ध तुरन्त कठोर कार्यवाही करने की मांग की है ।

वैसे इस प्रकरण की जांच करने के बाद ही कुछ उत्कृष्ट नतीजे पर पहुंचा जा सकता है, पर प्रशासन को तुरन्त कोई सही कदम उठाना चाहिए ताकि ऐसे प्रकरण दुबारा सुनने या देखने में न आएं । उदयपुर के अखबारों द्वारा चुप्पी भी आश्चर्यप्रद हैं ।

—सं. (नव जोति से)

क्रान्ति का पहला दिन—महिला दिवस

का. लेनिन ने कई बार 1917 की अक्टूबर क्रांति में महिलाओं द्वारा अदा की गयी भूमिका की प्रशंसा की थी। प्रथम विश्वयुद्ध से सोवियत महिलाओं के जीवन में नाटकीय परिवर्तन आया था जिसके फलस्वरूप वे अपनी निजी पारिवारिक भूमिका से निकलकर फैक्ट्रियों, अस्पतालों, युद्ध मोर्चों व गलियों में एक नयी सामाजिक भूमिका की ओर अग्रसर हुईं।

युद्ध के लिए लामबन्दी के पहले माह में ही लगभग 40 प्रतिशत सोवियत पुरुषों को औद्योगिक नौकरियां छोड़नी पड़ी थीं, जिनमें से अनेक को महिलाओं ने किया था। औद्योगिक उत्पादन के क्षेत्र में महिलाओं का यह प्रवेश एक प्रगतिशील चिह्न था तथा इससे उनके आर्थिक व राजनीतिक संगठन का आधार तैयार हुआ। इस बात का उल्लेख किया गया है कि अक्टूबर क्रान्ति के समय बोल्शेविक पार्टी के कुल सदस्यों में लगभग 10 प्रतिशत महिलाएं थीं व उन्होंने पार्टी संगठन के प्रत्येक स्तर पर प्रतिनिधि भूमिका निभायी थी।

1916 में युद्ध आरंभ होने के बाद पेत्रोग्राद में रोटी के लिए लोगों की मीलों लम्बी कतारें लगने लगीं थीं, जिनमें अधिकांश महिलाएं होती थीं। इस परिस्थिति में बोल्शेविकों ने हस्तक्षेप किया तथा युद्ध व खाद्य सामग्री के संकट की जिम्मेदारी प्रशासन पर डाली। इससे युद्ध-पीड़ित जनता की ओर से तीखी प्रतिक्रिया हुई।

प्रेस में तथा दीवारों पर ये नारे प्रकट हुए "युद्ध के दानव ने हमारे मजदूर संगठन को नष्ट कर दिया है··· सरकार ने हमारे पुरुष व स्त्री मजदूरों के साथ क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया है, हमारे पुत्र, पति व भाई विदेशी भूमि पर खून से लथपथ हैं व नये बाजार व अधिक भूमि की भूख की कीमत अदा कर रहे हैं···

···क्या यह संभव है हम विरोध में अपनी आवाज न उठायें, क्या सैकड़ों हजारों अभागी बहनें, माएं व पत्नियां विरोध में आवाज न उठायें? क्या हम अपने पुरुषों के दर्द के लिए निःशब्द आंसू बहाती रहें और घुटी-घुटी सिसकियां लेती रहें? यह नहीं हो सकता। सभी देशों में मजदूर राज्य द्वारा शोषण के खिलाफ उठ खड़े हुए हैं। हम भी इसका विरोध करते हैं और हमारी आवाज यह प्रदर्शित करती है कि हम बच्चों, भाइयों व पतियों की रक्षा कर सकती हैं।"

फरवरी क्रान्ति की एक चश्मदीद गवाह पित्रिम सोरकिन ने अपनी डायरी में लिखा है "यदि भविष्य के इतिहास क्रान्ति की शुरुआत करने वाले तबके की तलाश करते हैं तो वह भोजन की मांग करते हुए भूखे बच्चे व महिलाएं थीं।

सोरकिन ने शासन के पतन में महिलाओं की महत्व-पूर्ण भूमिका की ओर बिल्कुल सही इशारा किया है, लेकिन यह केवल आधी कहानी है। अनेक शहरों में कई माह से गलियों में महिलाओं के प्रदर्शन हो रहे थे। लेकिन ये प्रदर्शन स्थानीय गड़बड़ियों से अधिक कुछ नहीं थे, जिनसे बस कभी-कभार एक-आध दुकान लूटने की घटना घट जाती थी। लेकिन 23 फरवरी-अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस—1917 को हुआ बिल्कुल अलग तरह का था। ये जबर्दस्त शहर व्यापी प्रदर्शन थे। हजारों लोगों ने फैक्ट्रियों में काम रोक दिया, रेल रास्ते को रोक दिया व पुलिस द्वारा रोके जाने पर पुलिस पर हमला किया।

8 मार्च—अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस

सारी प्रगतिशील पार्टियों ने महिला दिवस को रैलियां करके, भाषण देकर व पर्चे बांटकर मनाने का मन बनाया था। एक भी संगठन ने हड़ताल की बात नहीं कही।

बहरहाल कुछ सौ कपड़ा मजदूर महिलाएं 23 तारीख की सुबह फैक्ट्री के बाहर एकत्र हुईं व उन्होंने 23 तारीख को एक दिन की राजनीतिक हड़ताल का फैसला किया। उन्होंने अपने प्रतिनिधि चुने व उन्हें आस पास की फैक्ट्रियों में समर्थन की अपील करने के लिए भेजा। संयोग से जिस समय ये महिला प्रतिनिधि एक फैक्ट्री में पहुंची उस समय पार्टी प्रतिनिधि कायुरोष वहां कॉरीडोर में चार मजदूरों से बात कर रहे थे संयोग से हुई इस भेंट के द्वारा ही बोल्शेविकों को इस आगामी राजनीतिक हड़ताल की जानकारी मिली। रोटी के लिए लम्बी होती कतारों ने ही हड़ताल को जन्म दिया। इससे एक बार फिर शासकों

की नीतियों के खिलाफ कार्रवाई में आगे आने में महिलाओं ने अभूतपूर्व उत्साह दिखाया।

23 तारीख की दोपहर तक लगभग 90,000 मजदूर हड़ताली महिलाओं के साथ हो चुके थे। अंततः बोल्शेविक पार्टी को भी इस हड़ताल के लिये सहमत होना पड़ा।

जैसे ही हड़ताली मजदूरों ने—जो अधिकतर विबोर्ग-नितो के थे—शहर में अपना जुलूस निकाला तो रोटी के लिए कतारों में खड़ी हजारों महिलाएं उनके साथ आ मिलीं। वे लोग साथ-साथ म्यूनिसिपल ड्रमा के पास भोजन की मांग करने गये।

दिन के बाकी समय में गलियां जनता से भर गयीं। हर जगह तुरन्त मीटिंगें हुईं, जल्दबाजी में तैयार किये गये लाल बैनर तान दिये गये व जनता ने शान्ति, अधिक वेतन व भोजन की मांग की। अन्य मांगें जल्दबाजी में सड़क पर चलने वाली कारों पर घसीट दी गयीं—"हमें रोटी दो", तथा "रोटी नहीं तो काम नहीं" आदि। एक महिला कंडक्टर के० लाकोरेबोई ने बताया "जब हम रात के पैसे जमा कराने गये तो वहां राइफलें लिए हुए सैनिक तैनात थे। अगले दिन भी वे वहीं थे।" कार-कंडक्टर हड़ताल के एक सफल नेता लेनोव (बोल्शेविक) ने हमसे कहा कि यह सब हमारे लिए है। आज पेत्रोग्राद में 2,00,000 कंडक्टर हड़ताल पर हैं।"

"जैसे ही हम यार्ड से बाहर निकलकर म्यूनिसिपल कारों में सवार होने के लिए बढ़े कि अचानक मजदूरों का एक झुंड गेट खोलने के लिए चिल्लाते हुए हमारी तरफ आया। वे सत्तर लोग थे। वे पटरियों पर तथा यार्ड के पीछे, गोर्नी म्यूजियम की सीढ़ियों पर खड़े थे। वे पाइप प्लांट, व कागज़ फैक्ट्री के मजदूर थे। उन्होंने हमें बताया कि आज शहर में हड़ताल है तथा सार्वजनिक कारें नहीं चल रही हैं। हड़ताली मजदूर कार चालकों को प्रबंधकों के हाथों से मुक्त कर रहे थे। चारों ओर से हमें सुनाई दिया "हमें रोटी चाहिये", "युद्ध-मुर्दाबाद" इसी बीच एक महिला चिल्लाई "हमारे पतियों को लाम पर से वापस बुलाओ।"

"हड़ताली मजदूर पूरे शहर भर में फैल गये। पुतिलोव फैक्ट्री से मजदूरों का एक प्रदर्शन हुआ, व बाढ़ की तरह मजदूरों के झुंड के झुंड आकर उसमें मिलते चले गये।

कुल मिलाकर दिन बिना किसी खास हिंसा के गुजर गया है। पुलिस की मदद के लिए सेना की टुकड़ियों को बुलाया गया था, लेकिन यह महसूस किया गया कि उनकी आवश्यकता नहीं है तथा उन्हें वापस बैरकों में भेज दिया गया।

लेकिन यह उनकी गलती थी। आने वाले दिनों में विरोध प्रदर्शन न केवल जारी रहा बल्कि और अधिक हिंसक रुख लेता गया जब तक कि रोमानोव साम्राज्य ढह नहीं गया।

एक के बाद एक घटनाओं की श्रृंखला को जन्म देने वाली हमारी हड़ताल के एक सप्ताह बाद प्रावदा ने अपने एक संपादकीय में लिखा :

"क्रान्ति का पहला दिन—महिला दिवस-अंतर्राष्ट्रीय कामगार महिला दिवस है। पत्रोग्राद की सड़कों पर सबसे पहले उतरने वाली महिलाएं थीं।"

अक्टूबर क्रान्ति की ओर

लेनिन के सोवियत संघ लौटने के तुरन्त बाद अप्रैल 1917 में लिखा गया "हमारी क्रान्ति में सर्वहारा का दायित्वः प्रोलिटेरियन पार्टी कार्यक्रम कहता है :

"जब तक महिलाओं को न केवल आम राजनीतिक जीवन में बल्कि रोजमर्रा की सार्वजनिक सेवाओं में आगे नहीं लाया जाता तब तक समाजवादता दूर की बात, पूर्ण-स्थायी लोकतंत्र की बात करना भी बेकार है। और 'बेघर बच्चों व बीमारों की देखभाल, भोजन निगरानी आदि जैसी सेवायें तब तक ठीक से नहीं चल सकतीं जब तक कि महिलाओं को न केवल कागजी तौर पर बल्कि वास्तव में आगे नहीं लाया जाता।"

1917 के वसन्त व शरद के पूरे पखवाड़े बोल्शेविकों ने महिलाओं के बीच अपनी गतिविधियाँ तेज कर दीं। लेनिन के सुझाव पर हुये पहले महिला सम्मेलन में, जिसमें मेन्शेविक, सामाजिक क्रान्तिकारियों व बोल्शेविकों ने भाग लिया; बोल्शेविकों में कामगार महिलाओं का विश्वास अभिव्यक्त हुआ।

अपने भाषण में बोल्शेविक पार्टी के एक प्रमुख नेता कोनोरिया सोमोलोव ने प्रस्ताव किया कि अब उद्योगों में महिलाओं के बीच किया जाने वाला सारा काम बोल्शेविक संगठनों के दिशा-निर्देश में होना चाहिये। स्वाभाविक रूप से इस प्रस्ताव का अन्य प्रगतिशील संगठनों की ओर से

कड़ा विरोध हुआ। बाकाशेवा (मेंशेविक) ने कहा कि महिला आंदोलन स्वतंत्र है और उसे किसी राजनीतिक पार्टी के अंतर्गत नहीं लाया जाना चाहिए। हालांकि, दो-चार महिलाओं ने मेंशेविक सुझाव का समर्थन किया, लेकिन बोल्शेविक नेतृत्व का प्रस्ताव ही स्वीकार किया गया। एक के बाद एक होने वाली घटनाओं के दबाव में अक्टूबर के पूर्ववर्ती महीनों में वाम-पंथियों में वैर-भाव बेहद बढ़ गया। जुलाई में एक महत्वपूर्ण घटना घटी। जब वर्ग-भेद हुआ तो बोल्शेविकों ने अपने को सर्वहारा की पहली पंक्ति में रखा। एक रूसी महिला उद्यमी ने याद करते हुए कहा : "मुझे याद है हम कैसे जुलाई के प्रदर्शन के लिए गये थे। हमारे संगठित पुरुष व महिला मजदूर बोल्शेविक झंडे तले उठ खड़े हुए। बुलन्द आवाजों से हमने कहा "हम; जो कुछ भी नहीं थे, और जो अब सब कुछ हैं; एक नये और बेहतर विश्व का निर्माण करेंगे।"

"जैसे ही प्रदर्शन नेवेंस्की और सेडोवा के कोनों की ओर बढ़ा, मशीनगनों की आवाज सुनायी दी। लोग बचने के लिए भागे, लेकिन चूंकि पहरेदारों ने सभी दरवाजे बन्द कर दिये उसके लिए भागने के लिए कोई रास्ता नहीं बचा था। गोलीबारी जारी रही। नेवेस्की प्रदर्शनकारियों की लाशों से पट गयी। नेवेस्की के एक कोने में भूमितल में एक स्टोर बना था। जैसे ही गोलीबारी शुरू हुई हमने स्टोर के बन्द दरवाजे से एक सीढ़ी लगा दी। महिलाएं एक दूसरे की मदद करती हुई खिड़की से दुकान के अन्दर चली गयीं और वहां से एक अंधेरी से भागकर चार्ड में पहुँची और वहां पुनः एक रास्ते से नेवस्की आ गयीं।"

"पेत्रोग्राद की सड़कें मजदूरों और सैनिकों के खून से रंग गयी थीं। हमने उन्हें एक सामूहिक कब्र में दफनाया।"

अक्टूबर के अन्तिम सप्ताह में बोल्शेविक पार्टी ने महिलाओं को संगठित कर उन्हें तत्काल संघर्ष में शामिल करने का जोरदार अभियान चलाया। पार्टी समिति ने महिलाओं का सम्मेलन किया जिसमें महिलाओं ने अपनी समस्याएं रखीं, पार्टी की ओर से प्रचलित अफवाहों को दूर किया गया, प्रति-क्रान्तिवादियों का विरोध किया गया महिलाओं में वर्ग चेतना के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए प्रयास करते हुए उन्हें क्रान्तिकारी गतिविधियों में लाने के प्रयास किये गये।

अक्टूबर क्रान्ति के साथ ही पेत्रोग्राद में प्रथम अखिल शहर महिला सम्मेलन किया गया जिसका आयोजन "रैबोट्निट्सा कामगार महिलाओं" द्वारा किया गया था व जिसमें 80,000 महिलाओं द्वारा चुनी गयी 500 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। सम्मेलन का प्रमुख उद्देश्य पार्टी-इतर महिलाओं की विजय के बाद आने वाली सोवियत सरकार के कार्यक्रमों के लिए तैयार करना था। महिलाओं ने सरकार से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर विचार किया तथा माताओं के कल्याण से संबंधित विभिन्न योजनाएं तैयार की।

सम्मेलन में सैन्य विद्रोह से अस्थायी तौर पर बाधा उत्पन्न हुई, जिस पर विचार चलता रहा था। प्रतिनिधियों ने क्रान्तिकारी गतिविधियों में सम्मिलित होने के लिए अवकाश लिया। उन्होंने अन्य सशस्त्र महिलाओं का साथ दिया, खदानें खोदीं व घायलों की सुश्रूषा की। अन्त में लेनिन ने उनके बारे में कहा :

"पेत्रोग्राद में, यहां मॉस्को में, शहरों में, औद्योगिक केन्द्रों में व देश के अन्य भागों में सर्वहारा महिलाएं क्रांति की परीक्षा में खरी उतरी हैं। उनके बिना हम यह संघर्ष नहीं जीत सकते थे। यह मेरा विचार है कि वे कितनी बहादुर थीं, कितनी बहादुर हैं। कल्पना कीजिये उन कष्टों की जो ये झेलती हैं। और वे डटी रहीं क्योंकि वे आजादी तथा साम्यवाद चाहती हैं। हां, बेशक हमारी सर्वहारा महिलाएं अप्रतिम वर्ग योद्धा हैं। वे प्रशंसा व प्रेम की पात्र हैं ..।" —'क्रान्ति व महिलाएं' से कुछ अंश

भिलाई महिला श्रमिक संघ का धरना

भिलाई महिला श्रमिक संघ दास्ताना इकाई की श्रमिक सदस्याएं अपनी मांगों को लेकर 23-10-91 से धरने पर तथा 8-11-91 से क्रमिक भूख हड़ताल पर बैठी हैं।

हिन्दुस्तान स्टील एम्प्लाइज यूनियन (सीटू), भिलाई महिला श्रमिक संघ को अपना समर्थन दे रहा है व उसे उम्मीद है कि महिलाओं की जायज मांगों को अवश्य मान लिया जायेगा।

इस संबंध में पी. के. मुखर्जी (संयुक्त सचिव) ने एक पत्र में आशा प्रकट की कि बातचीत के द्वारा जल्द ही मामले का कोई हल निकाल लिया जायेगा व औद्योगिक शान्ति को बनाये रखा जायेगा।

सरकार के मुकरने की सांसदों द्वारा निन्दा

हाल ही में चार महिला सांसदों; गीता मुखर्जी (भाकपा), सुशीला गोपालन व मालिनी भट्टाचार्य (माकपा), तथा जनता दल की सरोज दूबे ने एक प्रेस वक्तव्य में राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में श्रीमती सुशीला गोपालन द्वारा छेड़ी गयी आधे घंटे की बहस पर महिला व बाल कल्याण राज्य मंत्री द्वारा दिये गये उत्तर की तीखी आलोचना की। उन्होंने इसे दोमुंहापन का उदाहरण बताया।

श्रीमती गोपालन ने प्रश्न उठाया कि सरकार महिला आयोग प्रावधान अगस्त 1990 के अनुसार एक स्वतंत्र, स्थायी व बहुसदस्यीय संस्था के रूप में महिला आयोग का गठन करने में; जिसे महिला कानूनों की समीक्षा करने व उनमें बदलाव के बारे में राय देने का अधिकार हो; असमर्थ क्यों है। सुधीर गिरि, सुबोध दूबे तथा मालिनी भट्टाचार्य सहित अनेक सांसदों ने उनका समर्थन किया तथा मांग की कि इस सर्वसम्मति से पास हुए प्रावधान को तुरन्त लागू किया जाये।

ध्यान रहे कि राज्य मंत्री ने अपने जवाब में यही कहा है कि इस पर कोई फैसला नहीं लिया गया तथा वे मूल प्रश्न से साफ बच निकलीं कि प्रावधान को लागू करने में बाधा क्या है।

बहरहाल पहले महिला अधिकार आयुक्त कार्यालय की स्थापना संबंधी वक्तव्य से आशंका उत्पन्न होती है कि प्रावधान के कार्यान्वयन में बाधा क्या है। उल्लेखनीय है कि केन्द्र में आयुक्त कार्यालय के गठन का विचार 1988 में कांग्रेस (ई) द्वारा राष्ट्रीय आयोग हेतु राष्ट्रीय महिला योजना के मसौदे के अन्तर्गत रखा गया था। तब यह महसूस किया गया था कि ऐसी कोई संस्था तभी कारगर हो सकती है जब वह सरकारी अंकुशों से स्वतंत्र हो। यदि महिलाओं की देशव्यापी समस्याओं को सुलझाना है तो शक्ति किसी सरकारी अधिकारी के हाथों में सीमित नहीं होनी चाहिए। सांसदों का कहना है कि सरकार आयोग का गठन करने में इस लिए हिचकिचा रही है क्योंकि उसे स्वायत्तता प्रदान करनी होगी। यही वजह है कि पहले ही नामंजूर हो चुके आयुक्त कार्यालय के विचार पुनः रख रही है।

महिला प्रावधान अगस्त 1990 केवल संसद की सर्वसम्मति से ही नहीं बना बल्कि देश भर में महिलाओं की आकांक्षा व विश्वव्यापी महिला आन्दोलन का भी प्रतिनिधित्व करता है। सांसदों ने चेतावनी दी कि यदि सरकार प्रावधान को लागू करने में आनाकानी करती रही तो यह मुद्दा संसद के बाहर भी उठाया जायेगा।

असामाजिकता के खिलाफ जनता का प्रदर्शन

7 जुलाई 1991 को भागपुरना की एक पन्द्रह वर्ष की बच्ची का अपहरण करके उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया। 8 जुलाई को पुनः एक लड़की के साथ बलात्कार हुआ। हालांकि लड़की के पिता ने स्थानीय पुलिस से शिकायत की लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की हालांकि अपराधी जाने-पहचाने थे। भागपुरना के लोगों ने एक समिति गठित की तथा 15-8-91 को पांच हजार लोगों की जबर्दस्त रैली की। 20-8-91 को जब लोग फिर प्रदर्शन कर रहे थे तो पुलिस ने उनपर निर्ममता-पूर्वक लाठीचार्ज किया व हवा में गोलियां चलायीं। 29-8-91 को संघर्ष समिति ने मोगा के एस. डी. एम. कोर्ट के सामने धरना दिया व एक ज्ञापन भी दिया।

इसके बाद पुलिस लड़की को अदालत ले गयी लेकिन उससे पहले उसे पीटा व बनावटी वक्तव्य देने के लिए मजबूर किया। लेकिन इसके बाद लड़की ने एक प्रेस वक्तव्य में अपने अपहरण की सही कहानी सुनायी। उसने अपहरण व बलात्कार का पांच लोगों पर आरोप लगाया। लोगों ने 16-9-91 को फिर से शहर में प्रदर्शन किया व दोषियों की गिरफ्तारी की मांग की। साथ ही लाठीचार्ज व गोलीबारी के लिए जिम्मेदार लोगों की गिरफ्तारी की भी मांग की।

पांडिचेरी आंगनवाड़ी महिलाओं का बोनस के लिए अनशन

पांडिचेरी में बोनस की मांग कर रही आंगनवाड़ी महिलाएं 3 दिन से अनशन पर हैं। उनके निम्न वेतन मागों को देखते हुए उनकी मांगों को स्वीकार किये जाने का अनुरोध करते हुए एक ज्ञापन मुख्य मंत्री तथा समाज व कल्याण मंत्री को दिया गया। अखिल भारतीय आंगनवाड़ी फेडरेशन के अध्यक्ष की ओर से बोनस प्रदान किये जाने संबंधी तार भी 31.10.91 को मुख्यमंत्री को भेजा गया था।

"19.8.91 को आंगनवाड़ी सेविकाओं व सहायिकाओं की एक रैली के बाद, पांडिचेरी, समाज कल्याण मंत्री को एक ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में हमने मांग की कि संयुक्त बाल विकास योजना के तहत कार्यरत आंगनवाड़ी महिलाओं को बोनस/एक्स-गेसिया; 600/- व 900/- क्रमशः भुगतान किया जाये। मंत्री महोदय ने हमारी बात को ध्यान से सुना तथा हमरी समस्या को गंभीरता से लेते हुए कहा कि किसी न किसी रूप में उनकी मांग मानी जायेगी। पिछले वर्ष मजदूर को 400/- तथा 200/- रु० का भुगतान भारत सरकार द्वारा निर्धारित व बोनस के रुके होने के नाम पर दिये गये थे।

केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए बोनस की घोषणा होने के बाद हम पुनः 16.10.91 को समाज कल्याण मंत्री से मिले। हमने मांग की कि हमारे लिए 20.10.91 तक बोनस की घोषणा की जाये। मंत्री महोदय ने पुनः दोहराया कि मांगें मानी जायेंगी। आज 20 तारीख है, लेकिन आइ. सी. डी. एस. कर्मचारियों के बोनस के संबंध में कोई घोषणा नहीं की गयी है।

राज्य कार्यकरिणी की आज कार्यालय में बैठक हुई जिसमें तय किया गया कि बोनस भुगतान की मांग को लेकर निम्नलिखित ध्यानाकर्षण कार्यक्रम चलाये जायें।

विधान सभा के समक्ष मांगों के समर्थन में 23.10.91 से 26.10.91 तक क्रमिक भूख हड़ताल पर बैठने का फैसला हुआ।

26.10.91 को 9.00 बजे से 6.00 सायं तक प्रशासक-कार्यालय के सामने अनशन।

पांडिचेरी व कराइकल में 27.10.91 को 9 बजे से 5.00 बजे तक विधानसभा के सामने अनशन।

यह भी फैसला किया गया कि यदि उपर्युक्त कार्यक्रम के बाद भी मांगें नहीं मानी गयीं तो बिना नोटिस दिये सीधे कार्यक्रम चलाया जायेगा।

हम आपसे एक बार फिर अपील करते हैं कि आप अपने आश्वासन को पूरा करें तथा हमें सरकार को धन्यवाद देने का अवसर प्रदान करें।

धन्यवाद !

भवदीय—
पी० शशिकला, सचिव

नगर निगम में महिलाओं के लिए 30 प्रतिशत सीटें

नगरनिगमों के लिए होने वाले चुनावों में पहली बार महिलाओं की 30 प्रतिशत सीटें आरक्षित की गयी हैं। चुनाव 24 नवंबर को होंगे।

विधान सभा के 288 सदस्यों में से केवल दो महिलाएं हैं। एम.पी.सी.सी. की पूर्व अध्यक्ष तथा ए.आई.सी.सी. केरल की प्रेक्षक श्रीमती प्रभा रॉय ने कहा कि कांग्रेस सरकार के इस कदम से महिलाओं का बहुत बड़ा कल्याण होगा। बहरहाल सभी पार्टियों को उपयुक्त उम्मीदवार के चुनाव की दिक्कत पेश आयेगी। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने आरक्षण का इस आधार पर विरोध किया था कि कुछ क्षेत्रों में महिलाएं कमजोर उम्मीदवार रहेंगीं। उन्होंने कहा कि ऐसे भी उदाहरण हैं जब पुरुष उम्मीदवार कमजोर साबित हुए हैं।

उन्होंने कहा कि ऐसा संभव है कि कुछ पुरुष राजनीतिक आरक्षित स्थानों से अपनी पत्नियों को चुनाव लड़ावायें। उन्होंने महसूस किया कि महिलाओं में और अधिक जागरूकता होनी चाहिए। भाजपा के राज्य महासचिव धर्मचन्द कोडिया ने कहा कि उनकी पार्टी को महिला उम्मीदवार चुनने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अधिकतर प्रशासनिक संस्थाओं में कांग्रेस का प्रभुत्व है। चुनाव में पहली बार शिव सेना के उतरने के कारण कुछ स्थानों पर काटे का संघर्ष होगा। बहर हाल, शिव सेना के चरित्र को देखते हुए तथा नेतृत्व में महिलाओं को स्थान देने से उसके इनकार को देखते हुए उसे महिला उम्मीदवारों के संबंध में समस्या हो सकती है। सरकार राज्य में जिला परिषदों व नगरनिगमों के चुनावों को लगातार टालती आयी है व इससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया को धक्का पहुंचा है। विभिन्न पार्टियों के नेता भी इन संस्थाओं के हाथ में शक्ति नहीं सौंपना चाहते चुनाव टालने के पक्ष में रहते हैं। (टाइम्स ऑफ इंडिया, लखनऊ)

27 सितंबर को शानदार दिल्ली मार्च

27 सितंबर को दिल्ली में सभी वर्गों के कामगार लोगों का अभूतपूर्व जमावड़ा हुआ। वाम-राष्ट्रीय मोर्चा पार्टियों की रैली दिल्ली में हुई अब तक की सभी रैलियों से बड़ी थी। लोगों की भारी संख्या से अल्पमत नरसिंह राव सरकार की आर्थिक, सामाजिक व विदेश नीति के प्रति जनता का गुस्सा प्रकट होता है। रैली में भारी संख्या में महिलाएं आयीं जिनमें से कई हिन्दी क्षेत्रों से थीं। कृषि, आंगनवाड़ी निर्माण उद्योग व सर्वाधिक शोषित उत्तर प्रदेश से आयीं महिलाओं को मुगलसराय व सत्यगढ़ में उतरना पड़ा। उन्हें बिना टिकट नहीं आने दिया। वे इन्जन के सामने लेट गयीं जिससे मजबूर होकर रेलवे अधिकारियों को उन्हें यात्रा की इजाजत देनी पड़ी। महाराष्ट्र से आयीं महिलाएं दो दिन की यात्रा करके 27 तारीख की सुबह दिल्ली पहुंचीं। दिल्ली में 27 तारीख को लाल झंडों की बाढ़ आ गयी थी।

रैली वामपंथी पार्टियों की पकड़ का शानदार प्रदर्शन थी। राजघाट पर कैंप में इतनी भीड़ थी कि जुलूस 8 बजे प्रातः आरंभ करना पड़ा। जुलूस का अगला हिस्सा 10.30 बजे बोट क्लब पहुंचा। एकता व बलिदान के प्रतीक पंजाब की टुकड़ी सबसे आगे थी।

रैली के प्रमुख मुद्दे अभूतपूर्व मूल्य-वृद्धि तथा जनता द्वारा झेली जा रही अन्य आर्थिक समस्याएं थीं। कांग्रेस (ई) ने अपने चुनाव घोषण पत्र में वादा किया था कि सरकार सत्ता सम्हालने के 100 दिन के भीतर कीमतों को जुलाई '90 के स्तर पर ले आयेगी। लेकिन कुछ नहीं हुआ। इसके विपरीत कीमतें लगातार बढ़ रहीं हैं। रैली से मजदूर वर्ग के संगठित संघर्ष में लोगों का विश्वास प्रतिपादित हुआ। वे मिलबंदी, निजीकरण, गरीबी तथा बेरोजगारी के खिलाफ थे। लोग सरकार को चेताने आये थे रोजगार पाना उनका हक है। सभी पार्टियों ने सरकार को चेतावनी दी कि मुद्राकोष व विश्व बैंक से उनकी शर्तों पर ऋण लेना देश को बेचने के समान है। किसानों तथा कृषि मजदूरों ने भूमि तथा भूमिसुधारों की मांग की। उन्होंने हरिजनों व पिछड़े वर्गों पर अत्याचार समाप्त करने की मांग की।

हजारों की संख्या में दिल्ली पहुंची महिलाएं रोजगार, भूमि तथा सुरक्षा की मांग कर रही थीं। आंगनवाड़ी में महिलाओं को केवल 110/- रु० मिलते हैं तथा निर्माण उद्योग में प्रतिदिन 15-20 रु०। कृषि क्षेत्र में महिलाओं को 5 किलो गेहूं मिलता है। न्यूनतम वेतन का कोई प्रावधान नहीं है। देश भर में सैकड़ों महिलाओं की दहेज के लिए हत्याएं होती हैं। महिलाओं को राष्ट्रीय आयोग के लिए संघर्ष करना होगा।

रैली के प्रमुख वक्ता कॉ. हरिकिशन सिंह, सुरजीत (माकपा), ईन्द्रजीत गुप्ता (माकपा), वी. पी. सिंह (जनता दल), चित्त बसु (फॉरवर्ड ब्लाक) तथा नानी भट्टाचार्य (आर. एस. पी.) थे। राष्ट्रीय मोर्चे के नेताओं ने भी रैली को संबोधित किया। सभी वक्ताओं ने राम जन्म भूमि-बाबरी मस्जिद मामले पर भाजपा के रवैये की निन्दा की जिसने लोगों को धार्मिक आधार पर बांटा है।

रैली ने कॉ. फारुकी द्वारा रखा गया प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास किये। इसके अतिरिक्त का. सुरजीत द्वारा रखा गया 29 नवंबर की हड़ताल का प्रस्ताव भी ध्वनिमत से पारित हुआ।

संयुक्त सम्मेलन के रूप में विभिन्न उद्योगों व राज्यों में हड़ताल की तैयारियां जोरों पर हैं। यह हड़ताल कांग्रेसी सरकार को एक और धक्का पहुंचायेगी तथा चेतावनी देगी कि यदि वर्तमान नीतियां न बदली गयीं तो अल्पमत सरकार को भविष्य में एक बार फिर जनता का सामना करना पड़ेगा।

पढ़ें

कामकाजी महिला

(हिन्दी द्विमासिक पत्रिका)

कीमत : एक प्रति : 2 रुपये

वार्षिक चन्दा : 12 रुपये

अपनी प्रतियों के लिए हमें लिखें :

सी आई टी यू 6, ताल कटोरा रोड

नई दिल्ली-110001

प्रथम जीवन बीमा निगम कामगार महिला सम्मेलन
(रायपुर डिवीजन)

मध्य प्रदेश का छत्तीसगढ़ इलाका राज्य का सबसे अधिक पिछड़ा क्षेत्र है परन्तु इसी क्षेत्र के शहर रायपुर में मध्यमवर्गीय महिलाएं पहली बार एक ट्रेड यूनियन द्वारा आयोजित सम्मेलन में शामिल हुई एल. आई. सी. के रायपुर डिविजन में काम करने वाली करीब 150 महिलाओं ने इसमें हिस्सा लिया। सम्मेलन में न केवल रायपुर बल्कि जगदलपुर, बिलासपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, धन्तरी, कोरबा, आंतिकापुर महेंद्रगढ़, रायगढ़ व दंतवाड़ा से भी महिलाएं आयीं।

एल. आई. सी. की आल इण्डिया इन्श्योरेन्स एम्प्लॉइज यूनियन ने अखिल भारतीय स्तर पर अपनी महिला कर्मचारियों को संगठित करने व यूनियन में सक्रिय करने का "निश्चय किया है। इसी के तहत 8 सित० '91 को रायपुर डिवीजन की करीब 21 शाखाओं में काम कर रही 135 महिलाओं ने इस जीवन बीमा कामगार महिला सम्मेलन में भाग लिया।

सम्मेलन में कामगार महिला समन्वय समिति की केन्द्रीय कमेटी की सदस्य का० संध्या शैली उपस्थित थी। सम्मेलन का आरम्भ एक तीन सदस्यीय संचालन समिति के गठन से हुआ। कमेटी में कुसुम मिश्रा शालीनी टोपो व उषा परगनिया थी।

सम्मेलन में पहले खुले सत्र में अध्यक्ष मंडल के गठन के बाद रायपुर डिवीजन इन्श्योरन्स एम्प्लाइज यूनियन के महासचिव का. बी. सान्याल ने ट्रेड यूनियन का महत्व व कामगार महिलाओं द्वारा अपने ट्रेड यूनियन अधिकारों के प्रति सचेत रहने के औचित्य को रेखांकित किया। उन्होंने इन्शोरेन्स एम्पलाइज यूनियन द्वारा महिला कामगारों की सुविधा के लिये कामों व प्रयासों की जानकारी दीं। इसके बाद का. संध्या शैली ने सम्मेलन का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि देश में मौजूद पूंजीवादी अर्थव्यवस्था ने महिलाओं की स्थिति को बदतर बनाया है। इस समाज में जहां पुरुष के केवल श्रम का शोषण होता है वहाँ महिलाओं के श्रम व स्त्रीयोचितगुणों का भी शोषण होता है। सार्वजनिक क्षेत्र की कामगार मध्यमवर्गीय महिलाओं से लेकर कोयला खदान में गोटा बनाने वाली महिलाओं तक इसी शोषण का शिकार होती हैं। पूंजीवाद ने केवल अपने लाभ को बढ़ाने की सीमा तक महिला को अधिकार दिये हैं। स्त्री की वास्तविक मुक्ति समाजवाद में ही सम्भव है, जब वर्ग भेद व व्यक्तिगत सम्पत्ति का अन्त होगा।

उद्घाटन के बाद दूसरा सत्र प्रारम्भ हुआ। दूसरे सत्र में 135 महिला प्रतिनिधि शामिल थीं। ये प्रतिनिधि रायपुर के अलावा रायपुर से 300 कि. मी. दूर जगदलपुर से, बिलासपुर, दुर्ग राजनांदगाव, धमतरी, महासमुन्द, कोरबा, अंबिकापुर महेन्द्रगढ़, रायगढ़ और दन्तेवाड़ा तक से आई थीं।

इस सत्र के आरम्भ में आयोजन समिति की संयोजक कॉ. कुसुम मिश्रा ने रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट तीन हिस्सों में थी। पहले हिस्से में देश की वर्तमान आम कर्मचारी मजदूर व गृहिणी की हालत के बारे में बताया गया था दूसरे हिस्से में इन्श्योरेंस के कार्यालयों में नौकरी कर रही कामगार महिलाओं की परिस्थिति, उनकी संख्या व यूनियन द्वारा महिलाओं के लिए हासिल की गई सुविधाओं की ओर ध्यान आकर्षित कराया गया था। रिपोर्ट के अनुसार जीवन बीमा निगम में कामगार महिलाए पुरुषों का 25 प्रतिशत हैं। रायपुर मण्डल में यह प्रतिशत 26.31 का है। लेकिन अधिकारी वर्ग में एक भी महिला नहीं है। अभी पिछले दिनों जीवन बीमा निगम के प्रबन्धकों की ओर से महिला कर्मचारियों की एक प्रश्नावली बाँटी गई थी जिसमें ऐच्छिक सेवा निवृत्ति व महिला संगठनों के बारे में कुछ प्रश्न थे। निश्चय ही प्रबन्धकों के हेतु भला नहीं था परन्तु महिला साथियों ने इस प्रश्नावली को महत्व न देकर इसे नहीं भरा। उनका यह बर्ताव निश्चित रूप से ट्रेड यूनियन के प्रति उनकी वफादारी का प्रतीक था। रायपुर डिवीजन के नये भवन के निर्माण के समय महिला कर्मचारियों की सुविधाओं को ध्यान में रखने के प्रति प्रबंधक लापरवाही दिखा रहे थे। परन्तु यूनियन के समय पर किये गये हस्तक्षेप के कारण उन्हें खाने के कमरे, व अन्य सुविधाओं की व्यवस्था करनी पड़ी। रिपोर्ट के

तीसरे हिस्से में भावी जिम्मेदारियों की चर्चा थी। जिसमें स्पष्ट रूप से उन छोटे-छोटे नारी मुक्ति आन्दोलनों और नारी आश्रम-स्थलों को नकारा गया था और कामगार महिला के दोहरे शोषण के खिलाफ उठ खड़े होने के लिए यूनियन के संगठित संघर्ष को ही एक मात्र सही रास्ता माना गया था। रिपोर्ट में कामगार महिला और आम गृहिणी दोनों का आह्वान किया गया था कि उनकी मुक्ति का सही रास्ता श्रम जीवी जनता के व्यापक संगठनों से जुड़ कर इस पूंजीवादी व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष करने का रास्ता ही है।

रिपोर्ट पेश करने के बाद उस पर बहस प्रारम्भ हुई। बहस यद्यपि रिपोर्ट पर नहीं हुई परन्तु फिर भी जो महिलाएं बोलीं उन्होंने अपनी शाखा की कमियों की ओर ध्यान आकर्षित कराया। बहस में बीस महिलाओं ने हिस्सा लिया।

भिलाई की कॉ० शिप्रा राय ने वर्तमान समाज में महिलाओं के होने वाले दोहरे शोषण पर जोर दिया। इसके अलावा उन्होंने काम के घण्टों में बिना वृद्धि किये पाँच दिन के सप्ताह की मांग की। इसके अलावा 6 माह का मातृत्व अवकाश व उसके अगले 6 माह आधे वेतन पर अवकाश की मांग रखी जिसका महिलाओं ने तालियों के साथ समर्थन किया। महिलाओं को नौकरी के दौरान स्थानांतरण के समय होने वाली परेशानी का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इस नीति में महिलाओं के मामले में लचीलापन होना चाहिये।

बहस में बोलने वाली अन्य महिलाएं

रायपुर से शालिनी टोप्पो, सुशमिता डे, रोहिणी पिम्पलंगाकर जो अपनी शाखा की यूनियन सचिव भी है, कविता श्यामाबाई व संध्या मजूमदार थी। कविता ने अपने वक्तव्य में आरोप महिलाओं पर भी लगाया कि वे यूनियन से तो अपेक्षा करती है कि वह महिलाओं की समस्याओं की ओर ध्यान दे लेकिन महिलाएं खुद यूनियन की गतिविधियों के प्रति उदासीन रहती है। उन्हें यदि सुविधायें लेनी है तो यह उदासीनता भी खत्म करनी होगी।

भिलाई से अन्जना शीरे, उषा कुमारी, अनीता केलकर, यशोधरा कायसे ने अपनी शाखाओं की समस्याओं की ओर ध्यान दिलाया विशेष रूप से छोटे कॉमन रूप, बैठने की गलत व्यवस्था से कर्मचारी महिलाओं को होने वाली परेशानियां उन्होंने बताई। रायगढ से आई अन्जू पाण्डे, कोरबा की सरोजीनी कुजुर, भाटापारा की सुजाता गायकवाड़, महासमुंद की स्वर्णलता अवधिया बिलासपुर की जी. आर. पद्मा व राजनांदगांव की प्रमिला नागवंशी ने बड़े उत्साह से इस सम्मेलन का स्वागत किया और अपनी परेशानियों को बताने के साथ यह भी निश्चय प्रकट किया कि वे इन परेशानियों को यूनियन की सहायता से दूर करने के लिये संघर्ष करेंगी। भिलाई की उषा परगनिया ने बहस में हिस्सा लेते हुये रिपोर्ट का समर्थन किया और कहा कि यह सम्मेलन हमारे संघर्ष की शुरुआत है। रायपुर से 300 कि. मी दूर जगदलपुर से आई हुई महिला प्रतिनिधि का. अन्जली पाठक ने एक कविता के द्वारा कामगार महिला की परिस्थिति का वर्णन किया।

अन्त में का. कुसुम मिश्रा ने इस बहस का जवाब दिया। रिपोर्ट को महिलाओं ने तालियों की गड़गड़ाहट के साथ पारीत किया और आशा व्यक्त की कि महिलाएं जिस उत्साह से इस सम्मेलन में आयीं हैं वह उत्साह बना रहेगा और यूनियन की गतिविधियाँ बढ़ाने में काम आयेगा। अन्त में रायपुर डिवीजन इन्शोरेंस एम्पलॉइज यूनियन के महा सचिव का. बी. सान्याल ने जो पूरे सम्मेलन के दौरान उपस्थित थे, महिलाओं को अपना सम्मेलन समय सीमा के अन्दर समाप्त करने, मुद्दों पर बोलने और बड़ी संख्या में महिला वक्ताओं के सामने आने पर धन्यवाद दिया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जब तक महिलाएं यूनियन के प्रति, उसकी गतिविधियों के प्रति सकारात्मक रूख नहीं अपनायेंगी यूनियनें उनकी समस्याओं के प्रति उदासीन रहेंगी और वह स्थिति यूनियन के भविष्य के लिए खतरनाक साबित होगी। अखिल भारतीय स्तर पर ऑल इण्डिया इन्शोरेंस एम्प्लाइज यूनियन ने इसी लिये महिलाओं के स्थान-स्थान पर सम्मेलन आयोजित करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि रायपुर में एल. आई. सी. के इस सम्मेलन के बाद महिलाओं की एक सब कमेटी बनाई जायेगी जो अगले दो वर्ष तक काम करेगी। अगले सम्मेलन में एल. आई. सी. की हर शाखा अपनी एक महिला प्रतिनिधि भेजेंगी और फिर उस सम्मेलन में अगले दो वर्षों के लिए एक सब कमेटी चुनी जायेगी। अन्त में उन्होंने महिलाओं को इस सम्मेलन को सफल बनाने के लिये यूनियन की

रायपुर डिवीजन की ओर से धन्यवाद दिया। इसके बाद का. कुसुम मिश्रा ने सब कमेटी के लिए नाम प्रतिनिधियों के सामने रखे। प्रतिनिधियों ने हाथ उठाकर इन नामों को पारित किया। बनी हुई सब कमेटी में 6 सदस्य हैं कुसुम मिश्रा शालिनी टोप्पो, संध्या मुजूमदार, स्मिता गुहा, अनुसूया ठाकुर तथा सुशमिता डे।

सम्मेलन के अन्त में का. संध्या शैली ने बताया कि कामगार महिला समन्वय समिति को हाल में बनी सब कमेटी से क्या अपेक्षायें रहेंगी। उन्होंने आशा व्यक्त की कि एल. आई. सी. की महिलायें शहर की दूसरी कामगार महिलाओं को एक जुट करने में सहायक होंगी जिससे निकट भविष्य में विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत महिलाओं का एक सम्मेलन आयोजित किया जा सके।

अन्त में अध्यक्ष मण्डल की ओर से सम्मेलन समाप्ति की घोषणा कॉ. कुसुम मिश्रा ने की। सम्मेलन की विशेषता शाम को आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम था जिसमें एल. आई. सी. की महिलाओं ने ही विभिन्न कार्यक्रम पेश किये। इलेक्ट्रिक गिटार की धुन, गायन व इन कामगार महिलाओं के बच्चों द्वारा नृत्य ने माहौल को खुशनुमा बना दिया था लेकिन प्रमुख आकर्षण था "औरत" नाटक, जो एल. आई. सी. की धमतरी शाखा के कर्मचारियों द्वारा खेला गया।

(संध्या शैली)
सदस्य

अमरीका में बिगड़ती सामाजिक स्थिति

प्योंगयोंग टाइम्स, 20 सितंबर '91

हाल ही में अमरीकी प्रकाशनों, जैसे यू. एस. न्यूज तथा वर्ल्ड रिपोर्ट द्वारा प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार अमरीका में सामाजिक स्थिति खराब हो रही है।

इसकी प्रथम अभिव्यक्ति अमीर-गरीब के बीच बढ़ती खाई तथा बढ़ती हुई बेरोजगारी में होती है।

अमीर वर्ग की वार्षिक पारिवारिक आय जो कि समाज का 1% हिस्सा है—1977 में 203,000 थी। 1988 में ये आंकड़े बढ़कर 451,000 तक पहुंचे। इसके विपरीत इस अवधि में निम्न वर्ग की 1/5 पारिवारिक इकाइयों की आय में 10 प्रतिशत की कमी हुई।

1990 के अंत में बेरोजगारी की दर 7 प्रतिशत थी जबकि इस वर्ष जून में यह बढ़कर 7 प्रतिशत हो गयी। पूर्णतः बेरोजगारों की संख्या 9 मिलियन तथा अर्द्ध बेरोजगारों की संख्या 6.5 मिलियन पहुंच गया।

शहर में भीख मांगते हुए घूमने वालों की संख्या 2 मिलियन है।

8 वर्ष के 12 बच्चों में से 1 भूखा है व उनकी कुल संख्या 2 मिलियन है।

1-12 वर्ष के कुल बच्चों में से एक चौथाई बच्चे कुपोषण के शिकार हैं।

शिक्षा का स्तर गिर रहा है तथा अपराध बढ़ रहे हैं।

उच्च-माध्यमिक स्तर के अंतिम वर्ष के आधे बच्चे वह सब समझने में नाकाम हैं जो 8 वर्ष के लिए निर्धारित है। केवल 5 प्रतिशत बच्चे महाविद्यालयों की प्रवेश परीक्षा देने की स्थिति में हैं तथा 77 बच्चे रेस्त्रां में में उपलब्ध तीन प्रकार की चीजों की कीमतें जोड़ना नहीं जानते। कुल अपराधों में से 60 प्रतिशत अपराध हथियारों द्वारा होते हैं, तथा प्रतिवर्ष 34000 लोग उनके शिकार बनते हैं।

प्रत्येक पांच व्यक्तियों में से 2 व्यक्ति हिंसक अपराधियों के शिकार बनते हैं। प्रत्येक पांच में से तीन व्यक्ति भय व आशंका के शिकार हैं उनके घर अथवा पड़ोसियों पर हमला किया जायेगा।

कार-चोरी एक आय का साधन माना जाता है। पेशेवर कार-चोरों की बहुत बड़ी संख्या है। इन अपराधों को रोकने के लिए 'राष्ट्रीय कार चोरी ब्यूरो बनाया गया है लेकिन प्रत्येक 22 सैकिंड में एक कार चुरायी जाती है।

अमरीकी प्रकाशनों ने प्रशासन को 'नयी विश्व व्यवस्था' की बजाय 'नयी अमरीकी व्यवस्था' स्थापित करने का सुझाव दिया है।

तंजावूर क्षेत्र में कामगार महिलाओं का सम्मेलन

एल. आई. सी. की कामगार महिलाओं का तीसरा सम्मेलन भारतीय जीवन बीमा निगम रॉकफोर्ट इकाई के प्रांगण में 10-11-91 को सम्पन्न हुआ। सम्मेलन का विशेष महत्व ए. आई. आई. ई. एफ. की चालीसवीं वर्षगांठ के रूप में था। तंजावूर क्षेत्र के अंतर्गत सभी चार जिलों से काफी संख्या में सदस्यों ने सम्मेलन में भाग लिया। कामगार महिला समन्वय समिति की तमिलनाडु राज्य इकाई की राज्य समिति सदस्य का. कृष्णाबाई ने सम्मेलन का उद्घाटन किया।

कार्रवाई का संचालन एक अध्यक्ष मंडल ने किया जिसमें का. एम. सोलंकी, का. जे. उमा, का. के. कन्नामल शामिल थीं।

का. कृष्णा बाई ने अपने उद्घाटन भाषण में कामगार महिलाओं द्वारा किये गये विभिन्न संघर्षों का जिक्र किया। उनके भाषण में श्रमिक आंदोलन का उनका व्यापक अनुभव प्रतिबिम्बित हुआ।

सम्मेलन में भाग लेने वाले अधिकतर सदस्यों ने विचार-विमर्श में सक्रिय रूप से भाग लिया। अधिकतर सदस्यों ने कार्यालयों में विशेष रूप से महिलाओं की समस्याओं जैसे अलग शौचालय, आराम-गृह, भोजनालय आदि के बारे में बात की। इन सुविधाओं की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पास किया गया। लेकिन, विचार-विमर्श इसी स्तर पर समाप्त नहीं हुआ बल्कि उसने व्यापक रूप लिया। आम महिलाओं के उत्थान में कामगार महिलाओं की भूमिका पर भी विचार किया गया। आम महिलाओं के उत्थान व कल्याण के लिए भी एक प्रस्ताव बेहद उत्साह के साथ पास किया गया। आवागमन की अलग सुविधाओं की मांग करते हुए भी एक प्रस्ताव पास किया गया।

आई. सी. ई. यू. तंजावूर के अध्यक्ष का. के. लक्ष्मणन ने बात-चीत में उठे प्रश्नों का उत्तर दिया।

ए. आई. ई. ई. ए. के सह सचिव का. गोपाल राजन ने बात-चीत में उठे प्रश्नों का उत्तर रिया।

ए. आई. ई. ई. ए. के सह सचिव का. गोपाल राजन ने सम्मेलन का अभिनन्दन किया। उन्होंने आम महिलाओं व कामगार महिलाओं की समस्याओं, देश की वर्तमान स्थिति व सरकार की आर्थिक नीतियों का जिक्र करते हुए इनके खिलाफ आवाज उठाने का आह्वान किया। उन्होंने महिलाओं से अपील की कि वे 29 नवंबर की औद्योगिक हड़ताल को सफल बनाने के लिए काम करें।

का. सोलंकी ने धन्यवाद प्रस्ताव रखा व इसी के साथ सम्मेलन का समापन हुआ।

पंजाब में हत्याओं में वृद्धि

सदन को बताया गया कि चालू वर्ष में नवंबर तक पंजाब में 1,992 आम नागरिकों, 474 सुरक्षा कर्मियों व 2032 आतंकवादियों की हत्याएं हुईं।

श्री जैकब ने श्री दाऊ दयाल जोशी को बताया कि 1990 में राज्य में कुल 1974 आम नागरिकों, 493 पुलिस कर्मियों तथा 1321 आतंकवादियों की हत्याएं हुईं।

उन्होंने कहा कि हत्याओं की संख्या में आयी इस वृद्धि का कारण आतंकवादियों द्वारा चुनावों तथा राज्य में स्थिति सामान्य करने के अन्य प्रयासों को उलटने की कोशिश है।

हिन्दुस्तान टाइम्स, 10-12-91

"हरियाणा में महिला कर्मचारियों को छह माह का मातृत्व अवकाश"

चंडीगढ़ : हरियाणा के वित्त मंत्री श्री मांगे राम गुप्ता ने घोषणा की कि महिला कर्मचारियों को 1 जनवरी, 1992 से 20 दिन का आकस्मिक अवकाश प्रदान किया जायेगा, व इसमें नौकरी की अवधि की कोई शर्त नहीं होगी। इसके अतिरिक्त वर्तमान में दिये जाने वाले तीन माह के मातृत्व अवकाश के स्थान पर, दो जीवित बच्चों तक, छह माह का मातृत्व अवकाश प्रदान किया जायेगा।

हिन्दुस्तान टाइम्स, 11-12-91.

महिलाओं पर अत्याचार की भर्त्सना

महिलाओं के खिलाफ हिंसा के विभिन्न रूप लेने के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के लिए हाल ही में यहाँ सात राष्ट्रीय महिला संगठनों की बैठक हुई । बैठक में महिलाओं पर बढ़ते हुए जुल्मों की एक स्वर में भर्त्सना की गयी । यह बैठक विशेष रूप से निम्न मुद्दों पर केन्द्रित थी।

1. बर्मा में सैनिक शासन के अंतर्गत हुंग सान सू म्यी घर में नजरबंद हैं । सैनिक शासन द्वारा जन-अधिकारों की हत्या को शर्मनाक ढंग से नजरअंदाज किया गया है । विश्व-भर में 'खाकी वर्दी' की यही प्रवृत्ति है । स्वयं शासन ने भी इस बात से इन्कार नहीं किया है कि सुश्री म्यी चुनाव विजेता थीं । इसके बावजूद उन पर अत्याचार किये जा रहे हैं तथा बर्मा के सैनिक शासन द्वारा उन्हें राजनीतिक बन्दी बनाया गया है । प्रथमतः यह लोकतंत्र की हत्या है तथा यह उनके अधिकारों व स्वतंत्रता का उल्लंघन करके उनको मानसिक यातना देना है । यह एक व्यक्ति के रूप में उन पर अत्याचार है ।

हम; महिला संगठन; नोबल शान्ति पुरस्कार विजेता को उनके हिम्मत भरे प्रयासों के लिए बधाई देते हैं तथा लोकतंत्र के लिए उनके संघर्ष के प्रति अपना समर्थन व्यक्त करते हैं । साथ ही हम सुश्री सू. के खिलाफ किये जा रहे अत्याचारों की भर्त्सना करते हुए सैनिक शासन से मांग करते हैं कि वह जनता की भावनाओं का सम्मान करे ।

2. श्री म्लीयरेंस थॉमस के व्यवहार को उजागर करने के लिए हम सुश्री अनीता हिल को बधाई देते हैं, यौन छेड़-छाड़ एक अत्याचार है जिसकी अनेक महिलाएं शिकार हैं । कम महिलाओं में इतनी हिम्मत होती है । यह एक स्वागत योग्य बात है । अतः सोम बेनेगल की यह टिप्पणी कि "हमारे देश की 'अनीता हिलें' पर्वत बनना चाहती हैं" आपत्तिजनक है । हम निश्चित् रूप से ऐसे वक्तव्यों पर एतराज व्यक्त करते हैं जो महिलाओं से चुपचाप अत्याचार सहने की उम्मीद रखते हैं, हम अपने देश की ऐसी सभी 'अनीता हिलों' के प्रति अपना समर्थन व सहयोग व्यक्त करते हैं व उम्मीद करते हैं कि वे कल की 'पर्वत शिखर' होंगी ।

ज्वाइंट वोमेन्स प्रोग्राम
महिला दक्षता समिति
वाई. डब्ल्यू. सी. ए. ऑफ इंडिया
ऑल इण्डिया डेमोक्रेटिक वोमेन्स ऐसोसियेशन
नेशनल फेडरेशन ऑफ इण्डियन वोमेन
ऑल इण्डिया वोमेन्स कॉफ्रेंस
सेंटर फॉर वोमेन्स डेवलपमेंट स्टडीज

संसद समाचार

महिलाओं के खिलाफ बढ़ते हुए अपराध

"दहेज हत्याओं के 2,448 तथा बलात्कार के 5,916 मामले दर्ज"

नई दिल्ली, 9 दिसंबर । आज लोकसभा को बताया गया कि दहेज हत्याओं के 2448, बलात्कार के 5916, छेड़छाड़ के 12,902 तथा महिलाओं के अपहरण के 7,116 मामले इस वर्ष दर्ज हुए ।

गृह राज्य मंत्री एम. एम. जैकब ने श्री शरद धीशे के एक प्रश्न के एक लिखित उत्तर में बताया कि दहेज हत्या के सबसे अधिक मामले, 1152 उत्तर प्रदेश में दर्ज हुए । इसके बाद महाराष्ट्र (568) तथा आंध्र प्रदेश (305) का स्थान है ।

केन्द्र शासित प्रदेशों में हुई कुल 109 दहेज हत्याओं में से 103 दिल्ली में हुईं ।

बलात्कार के सर्वाधिक 1532 मामले मध्य प्रदेश में दर्ज हुए । इसके बाद उत्तर प्रदेश (922) तथा बिहार (403) का स्थान है । मध्य प्रदेश में छेड़-छाड़ की सर्वाधिक घटनाएं हुईं, व उसके बाद क्रमशः महाराष्ट्र व उत्तर प्रदेश हैं ।

हिन्दुस्तान टाइम्स, 10-12-91

उजन मैदान कांड के लिए सरकार को दोषी ठहराया

त्रिपुरा में 1988 में उजन मैदान में असम राइफल्स के जवानों द्वारा आदिवासी महिलाओं पर सामूहिक बलात्कार के आरोपों की जांच करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के जस्टिस देब की अध्यक्षता में एक जांच आयोग नियुक्त किया था। देश की सबसे बड़ी अदालत ने अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति की याचिका पर, यह जांच आयोग बैठाया था।

जस्टिस देब ने अब अदालत को अपनी रिपोर्ट दे दी है। उनकी रिपोर्ट, त्रिपुरा राज्य सरकार तथा सैनिक अधिकारियों को साफ तौर पर कटघरे में खड़ा कर देती है। इस लंबी रिपोर्ट का निष्कर्षात्मक अंश हम यहां प्रकाशित कर रहे हैं। रिपोर्ट, 1992 के मार्च में सुनवायी के लिए सर्वोच्च न्यायालय के सामने आएगी।

227. महिलाओं के खिलाफ अपराध हमारे देश में चिंताजनक रूप से बढ़ रहे हैं। कम से कम कोई तो ऐसा होना ही चाहिए, जो उनके सम्मान तथा पवित्रता की हिफाजत करने के पवित्र लक्ष्य को अपने हाथ में ले। सिर्फ इसलिए कि इस एसोसिएशन तथा सी पी आइ (एम) के कुछ सदस्यों ने उजन मैदान में शिकार हुई आदिवासी महिलाओं के हितों का मसला उठाया है, यह नहीं कहा जा सकता है कि उन्होंने राज्य सरकार या भारतीय संघ के खिलाफ कुछ किया है और वास्तव में यह बात तो, बार में एसोसिएशन तथा सी पी आइ (एम) के खिलाफ जो तर्क दिया गया है, उसकी जड़ ही काट देता है। अब वक्त आ गया है कि सम्मानित सर्वोच्च न्यायालय इस पर अपनी अमूल्य राय दे कि क्या अर्द्ध सैनिक बलों या सेना को, देश की किसी भी राजनीतिक पार्टी के खिलाफ कुछ कहने की इजाजत दी जानी चाहिए? इस अमूल्य राय का हमारे समूचे राष्ट्र तथा देश पर, दूरगामी असर पड़ेगा।

228. यहां मैं निम्नलिखित निष्कर्ष के साथ अपनी रिपोर्ट समाप्त करता हूं :—

(1) 31 मई तथा 2 जून 1988 के दौरान उजन मैदान में असम राइफल्स के कुछ जवानों ने कम से कम राधिका, वनपाती, सोनाकाली तथा सुभालक्ष्मी के साथ सामूहिक बलात्कार किया था और असम राइफल्स के एक जवान ने पंचलक्ष्मी के साथ जोर-जबर्दस्ती की थी। और,

(2) त्रिपुरा राज्य तथा सैन्य अधिकारी उक्त अपराधों पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं और पुलिस की जांच भी उसी दिशा में आगे बढ़ी है।

अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति ने 10 दिसंबर को जारी एक बयान में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त एस सी देब आयोग की रिपोर्ट का स्वागत करते हुए याद दिलाया कि समिति की उपाध्यक्ष विमल रणदिवे द्वारा समिति की ओर से दायर याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय ने यह आयोग नियुक्त किया था और इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट में त्रिपुरा सरकार, असम राइफल्स तथा फौज को, इस पूरे प्रकरण को दबाने की कोशिशों के लिए कड़े शब्दों में निंदा की है।

महिला समिति ने याद दिलाया है कि उस समय त्रिपुरा सरकार ने साफ तौर पर इससे इंकार किया था कि बलात्कार की ऐसी घटना हुई थी। जांच आयोग की इस रिपोर्ट के बाद, जनतांत्रिक नियम-कायदों का जरा-सा भी सम्मान करने वाली किसी भी सरकार ने इस्तीफा दे दिया होता। लेकिन, इस सरकार से तो ऐसी कोई उम्मीद की नहीं जा सकती है, जो किसी भी तरह अपनी सत्ता कायम रखना चाहती है और इसके लिए आदिवासी महिलाओं को आतंकित करने के लिए बलात्कार का राजनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने से भी गुरेज नहीं करेगी।

महिला समिति के बयान में रेखांकित किया गया है कि उजन मैदान सामूहिक बलात्कार कांड के बाद से त्रिपुरा में मुख्यतः आदिवासी महिलाओं पर ही बलात्कार के कम से कम 165 और कांड हुए हैं। और उजन मैदान कांड की ही तरह, इनमें से ज्यादातर मामलों में कोई एफ आइ आर तक नहीं दर्ज की गयी है और त्रिपुरा सरकार ने इन घटनाओं के होने से ही इन्कार कर दिया है।

महिला समिति ने यह मांग की है कि जांच आयोग की रिपोर्ट में फौज तथा असम राइफल्स के जिन अफसरों को दोषी ठहराया गया है, उन्हें समुचित दंड दिलाया जाय।

Book Post